राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष-47 ■ अंक-08 ■ दिसम्बर 2025 ■ ₹10 ■ पृष्ठ-44

ज्ञान शील एकता

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

ABVP

71वां राष्ट्रीय अधिवेशन

अभाविप

28,29 व 30 नवंबर 2025

भगवान बिरसा मुंडा नगर, देहरादून

सबको अवसर मिले निरंतर भाव स्वदेशी विकसित हो

राष्ट्रीय अधिवेशन की झलकियां

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष-47, अंक-08
दिसम्बर 2025

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक मण्डल
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

05 देवभूमि में भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक एकता का दर्शन

देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित परेड मैदान में...

संपादकीय	04
'ज्ञान, तकनीक और निडर शक्ति से होगा राष्ट्र का उत्थान'	10
76 लाख से अधिक हुई अभाविप की सदस्यता	12
'जेन-जी आंदोलन और भारतीय युवा'	14
'युवाओं से विकसित भारत का आह्वान'	15
'ज्ञान आधारित भारतीय शिक्षा परंपरा पर होना चाहिए विचार'	18
'राष्ट्रभाव से एकत्व के लिए कार्य कर रही है अभाविप'	20
प्रदर्शनी ने कराया रानी अब्बक्का के तेज और शौर्य से परिचित : आचार्य बालकृष्ण	24
भारत का बदलता सुरक्षा परिदृश्य	26
'संतुलित और संस्कारित जनसंख्या भी होना चाहिए विकसित भारत का लक्ष्य'	27
पारित हुए पांच प्रस्ताव	28
'स्क्रीन टाइम' कम करके 'नेशन टाइम' बढ़ाए युवा : श्रीकृष्ण पांडेय	30
राष्ट्रीय पदाधिकारी 2025-2026	32
राष्ट्र का उद्घोषक मंत्र है एकात्मता स्तोत्र	33
विश्वविद्यालयों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों में आतंकी मॉड्यूल : एक भू-राजनीतिक चेतावनी	35
India as an exporter of military hardware	38
लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुद्धता में एसआईआर की भूमिका	40

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

दिसंबर का महीना आमतौर पर वर्ष भर के लेखे-जोखे का होता है। प्रायः इसी समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन भी सम्पन्न होता है, जिसमें गत वर्ष की गतिविधियों का आकलन तथा आगामी वर्ष की योजना का निर्धारण किया जाता है।

अबकी बार राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में 28 से 30 नवंबर के मध्य सम्पन्न हुआ। अधिवेशनों की शृंखला में यह 71वां आयोजन था। प्रख्यात वैज्ञानिक तथा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संस्थान के पूर्व अध्यक्ष डा. श्रीधर पणिकर सोमनाथ ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी प्रतिष्ठित पुरस्कार 'यशवंतराव केलकर सम्मान' प्रदान करने के लिए उपस्थित थे। इस वर्ष यह पुरस्कार 'स्माइल रोटी बैंक फाउंडेशन' के अध्यक्ष श्रीकृष्ण पांडेय 'आजाद' को प्रदान किया गया।

परिषद कार्य को शिक्षा जगत में स्वीकृति का प्रमाण उसका अभूतपूर्व विस्तार है। गत वर्ष की तुलना में 17 लाख से अधिक वृद्धि के साथ शिक्षा सत्र में संगठन की सदस्य संख्या 76 लाख 98 हजार 4 सौ 48 हो गई है। वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की सहभागिता भी बढ़ी है। जिन विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव हुए, उनमें परिषद ने अधिकांश स्थानों पर विजय प्राप्त कर कीर्तिमान बनाया है।

अभाविप के संगठन शिल्पी स्व. यशवंतराव केलकर के जन्मशती समारोह के निमित्त देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके लिए अनेक प्रकार के आयोजन हुए, जिनमें यशवंत स्मरण, प्रिय केलकर जी अभिवाचन, यशवंत विद्यार्थी सत्कार समारोह, यशवंत वारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन तथा पंजाब में आयोजित 'हर वृक्ष में केलकर' जैसे आयोजन उल्लेखनीय हैं।

अधिवेशन से प्राप्त ऊर्जा को अपने कार्यक्षेत्र में नियोजित कर सभी कार्यकर्ता आगामी वर्ष के लिए निश्चित किए गए कार्यक्रमों को सफल करेंगे तथा 'पंच प्रण' को लेकर परिसरों में सक्रिय होंगे, जिससे परिसरों की जीवंतता बनी रह सके, वृद्धिंगत हो।

यशवंतशती के अतिरिक्त यह वर्ष राष्ट्रीय जीवन के अनेक आयामों को स्पर्श करने वाली विभूतियों के स्मरण से भी जुड़ा हुआ है। उल्लाल (कर्नाटक) की रानी अब्बक्का की पांच सौवीं जयन्ती, भगवान बिरसा मुण्डा के जन्म की सार्धशती, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के 350 वर्ष सहित अनेक महान पुरुषों और नारियों का उल्लेख किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की शताब्दी सम्पूर्ति का भी यह अवसर है।

बीसवी शती के भारत से जुड़ी दो घटनाएं भी कालक्रम में सिंहावलोकन का अवसर बनी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। पहला है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 में गठन, जिसके सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं और दूसरा आपातकाल का लागू किया जाना, जिसके 50 वर्ष गत 26 जून को पूरे हुए। यह दोनों घटनाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं को निरंतर जागरूक रहने और इतिहास से सबक सीखने के लिए प्रेरित करती हैं।

'समाज परिवर्तन का वाहक बने युवा', 'भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती है बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ', 'प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समाज से आगे आने का आह्वान', 'सभी शैक्षणिक संस्थाओं को एक संरचना के अंतर्गत लाने की आवश्यकता' तथा 'विभाजनकारी ताकतों के विरुद्ध संगठित हो भारतीय समाज' शीर्षक से पांच प्रस्ताव अधिवेशन में सर्वसम्मति से पारित किए गए। विद्यार्थी काल से ही परिषद से जुड़े डा. रघुराज किशोर तिवारी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, वहीं डा. वीरेन्द्र सिंह सोलंकी महामंत्री पद पर पुनः निर्वाचित हुए। विश्वास है कि अधिवेशन से प्राप्त ऊर्जा को अपने कार्यक्षेत्र में नियोजित कर सभी कार्यकर्ता आगामी वर्ष के लिए निश्चित किए गए कार्यक्रमों को सफल करेंगे तथा 'पंच प्रण' को लेकर परिसरों में सक्रिय होंगे, जिससे परिसरों की जीवंतता बनी रह सके, वृद्धिंगत हो।

शुभकामना सहित

आपका
संपादक

देवभूमि में भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक एकता का दर्शन

अभाविप का 71 वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न, शैक्षिक परिसरों में होगा सामूहिक वंदे मातरम् गान आयोजन

■ अजीत कुमार सिंह

देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित परेड मैदान में कई दिनों की मेहनत के बाद अस्थाई रूप से बसाए गए भगवान बिरसा मुंडा नगर का जब मूर्त रूप सामने आया, तो देखकर सभी अभिभूत थे। नगर का पूरा प्रांगण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से कार्यकर्ताओं के उत्साह, हर्ष, ऊर्जा एवं उल्लास से जीवंत हो उठा, तो स्थानीय निवासियों के लिए कौतूहल का कारण बन गया। राज्य की संस्कृति एवं देवभूमि के सजीव दृश्यों को प्रदर्शित करने वाले भगवान बिरसा मुंडा नगर में 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में 45 प्रांतों के प्रतिनिधि अपने-अपने पारंपरिक परिधान एवं वेशभूषा में सम्मिलित हुए।

उत्तराखंड में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ गत 28 नवंबर को प्रातः सामूहिक वंदे मातरम

रानी अब्बक्का कलश ने किया प्रेरित

अभाविप के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन प्रांगण भगवान बिरसा मुंडा नगर में रानी अब्बक्का की 500वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली कर्नाटक से निकाली गई रानी अब्बक्का कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। पवित्र जल कलश को राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में अभाविप के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. राजशरण शाही को सौंपा गया, जिन्होंने इसे प्रांगण में स्थापित किया। रानी अब्बक्का की जन्मस्थली से निकाली गई यह यात्रा कर्नाटक से आरम्भ होकर देहरादून स्थित अधिवेशन स्थल पहुंची। इस दौरान 20 विश्वविद्यालयों, 210 महाविद्यालयों तथा अन्य स्थानों से होते हुए यात्रा में तीन हजार किलोमीटर से अधिक दूरी तय की गई। पवित्र जल कलश को राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य आकर्षण केंद्र रानी अब्बक्का प्रदर्शनी में रखा गया। ■

गान से हुआ। अधिवेशन के लिए भगवान बिरसा मुंडा नगर के निर्माण में लगभग एक माह का समय लगा। जनरल विपिन रावत की स्मृति में अधिवेशन स्थल का मुख्य सभागार बनाया गया, तो नगर परिसर में रानी अब्बक्का की पांच सौवीं जयंती पर समर्पित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो भारत की वीरांगनाओं के साहस एवं बलिदान को दर्शाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में नारियों के योगदान की जीवंत कथा को सुना रही थी। ज्ञान, साधना, संस्कार और गंगा-यमुना के उद्गम स्थल की भूमि पर आयोजित अधिवेशन में एक अन्य सभागार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं अभाविप के पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री राधेश्याम जी को समर्पित किया गया।

भगवान बिरसा मुंडा नगर के परिसर में स्वामी विवेकानंद, स्वतंत्रता सेनानी-चिंतक विनायक दामोदर सावरकर, गुरु तेग बहादुर, धरती आबा बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमाएं अभाविप कार्यकर्ताओं में उमंग एवं राष्ट्र भक्ति का संचार करती हुई दिखाई दी, तो आपरेशन सिंदूर की झलक दिखाने वाली झांकी को देखकर हर कोई देश के वीर सैनिकों के लिए श्रद्धा भाव से नतमस्तक होने के लिए बाध्य हो गया था। अधिवेशन स्थल पर लगाए गए स्टालों में उत्तराखंड के परिधान, वेशभूषा, भोज्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं आकर्षण का केंद्र रही। 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन की पूर्व संध्या पर गत 27 नवंबर को रानी अब्बक्का पर केंद्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन पंतजलि योग ट्रस्ट के महासचिव आचार्य बालकृष्ण एवं उत्तराखण्ड सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने किया।

उद्घाटन के बाद आचार्य बालकृष्ण एवं डा. रावत ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तो वह भी रानी अब्बक्का की वीरता को नमन करने के लिए बाध्य हो गए। गत 27 नवंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु (झारखंड) से आरम्भ हुई "भगवान बिरसा सन्देश यात्रा' और रानी अब्बक्का की पांच सौवीं जयंती पर कर्नाटक स्थित उनकी जन्मस्थली से निकली "रानी अब्बक्का कलश यात्रा" का भव्य स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर अभाविप के निवर्तमान अध्यक्ष डा. राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सोलंकी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। दोनों यात्राओं के समापन अवसर पर भगवान बिरसा की जन्मभूमि से लाई गई पवित्र मिट्टी एवं पवित्र जल वाला रानी अब्बक्का कलश राष्ट्रीय पदाधिकारियों को सौंपा गया, जिसे नगर प्रांगण में स्थापित किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से लाए गए पवित्र जल-कलश का श्रद्धापूर्वक स्वागत कर मुख्य सभागार में प्रतिष्ठित किया गया, जिसने अधिवेशन को ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक

चेतना प्रदान की।

भगवान बिरसा सन्देश यात्रा एवं रानी अब्बक्का कलश यात्रा का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता में दोनों के अदम्य साहस एवं शौर्य की गाथा को सामने रखना और युवाओं को राष्ट्र कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करना रहा। वास्तव में देखा जाए दोनों यात्रा शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट संतुलन स्थापित करने में पूरी तरह सफल रही। यात्रा के समापन अवसर पर अधिवेशन स्थल पर एकजुट अभाविप के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी राष्ट्र प्रेम की भावना से सराबोर दिखाई दिए। अधिवेशन से पहले अभाविप की एक-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद और केंद्रीय कार्यसमिति बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करके आगामी कार्य रणनीति को अंतिम रूप दिया गया।

देवभूमि पर पहली बार आयोजित अभाविप के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन 28 नवंबर को हुआ। उद्घाटन से पहले निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही एवं राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सोलंकी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद हुए वंदे-मातरम के सामूहिक गान से पूरा नगर परिसर गूंज उठा। अपने-अपने प्रांत के

अभाविप चलाएगी 'स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम' अभियान

आगामी वर्ष परिषद के लिए व्यापक कार्यक्रमों और राष्ट्रीय अभियानों का वर्ष होगा। अभाविप ने छात्रावास सर्वेक्षण, 'स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम' अभियान, महारानी अब्बक्का की 500वीं जयंती, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, आपातकाल के 50 वर्ष तथा 'वंदेमातरम्' के 150 वर्ष जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों को अपनी प्राथमिक गतिविधियों में सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न परिसरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बौद्धिक परिचर्चाओं, जनजागरण अभियानों और रचनात्मक पहलों के माध्यम से छात्र-समुदाय को सक्रिय, जागरूक और संगठित करने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे। परिषद की ओर से यह आशा व्यक्त की गई कि कार्यकर्ता आगामी वर्ष में भी संगठन के आदर्शों और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा, समाज और राष्ट्र-निर्माण के क्षेत्रों में प्रभावी योगदान सुनिश्चित करेंगे। ■

'भगवान बिरसा संदेश यात्रा' का समापन

अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन में भगवान बिरसा की जन्मस्थली झारखंड के उलिहातु से आरम्भ हुई "भगवान बिरसा संदेश यात्रा" का समापन भी हुआ। भगवान बिरसा संदेश यात्रा का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली झारखंड के खूंटी जिले स्थित (उलिहातु) से गत 15 नवंबर को भगवान बिरसा की प्रतिमा का माल्यार्पण एवं रथ पूजन के पश्चात हुआ। जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी को लेकर आरम्भ हुई 'भगवान बिरसा संदेश यात्रा' खूंटी, चक्रधरपुर, चाइबासा, सरायकेला, रांची, जमशेदपुर, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, मोदिनीनगर, गढ़वा, दुद्धी, रॉबर्ट्सगंज, वाराणसी, जौनपुर, कुशभवनपुर, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर होते हुए गत 27 नवंबर को अधिवेशन स्थल 'भगवान बिरसा मुंडा नगर' पहुंची। यात्रा के दौरान विराम स्थलों पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भगवान बिरसा द्वारा जनजातीय गौरव को बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों को आम जन तक पहुंचाया गया। संदेश यात्रा ने युवाओं के साथ ही संपूर्ण समाज को जल, जंगल और जमीन, आत्मसम्मान, सामाजिक एकता एवं राष्ट्रहित के प्रति संपूर्ण समर्पण की प्रेरणा देने में सफल रही। ■

खुले अधिवेशन में हुई घुसपैठियों को निकालने की मांग

अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई भव्य शोभायात्रा के बाद खुले अधिवेशन में वक्ताओं ने देश में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों को बाहर निकालने के साथ ही राष्ट्र हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार आम जनता एवं अभाविप कार्यकर्ताओं के सामने रखे। खुले अधिवेशन को राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सोलंकी, राष्ट्रीय मंत्री क्षमा शर्मा, प्रान्त मंत्री (उत्तराखंड) ऋषभ रावत, प्रांत मंत्री (विदर्भ) पायल किनाके, केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य सुब्रत अधिकारी, इंदुचूड़ नार, गौरव वीर सोहेल ने सम्बोधित किया। अपने सम्बोधन में वक्ताओं ने नक्सलियों का समर्थन करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ ही पश्चिम बंगाल की जटिल स्थितियों को सार्वजनिक करने के साथ ही अन्य राष्ट्रीय मसलों पर अपने विचार सामने रखे। ■

स्थानीय परिधानों में एकत्र हुए प्रतिनिधियों को देखकर लघु भारत का दर्शन हो रहा था। ध्वजारोहण के बाद वर्ष भर के कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री डा. सोलंकी ने जब यह घोषणा की कि अभाविप सदस्यों की संख्या 76 लाख पार कर चुकी है, तो जनरल विपिन रावत सभागार अभाविप कार्यकर्ताओं की हर्ष ध्वनि से गूंज उठा। महामंत्री प्रतिवेदन के बाद नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. रघुराज किशोर तिवारी एवं पुनः निर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सोलंकी ने अपने दायित्व को ग्रहण किया।

अभाविप के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन प्रख्यात वैज्ञानिक एवं भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष डा. श्रीधर पणिकर सोमनाथ ने किया। उद्घाटन समारोह में अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. रघुराज किशोर तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सोलंकी, मंत्री क्षमा शर्मा, स्वागत समिति अध्यक्ष डा. कमल घनशाला, उत्तराखंड अभाविप के प्रान्त अध्यक्ष डा. जे. पी. भट्ट एवं प्रान्त मंत्री ऋषभ रावत मंच पर उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डा. सोमनाथ ने अभाविप कार्यकर्ताओं को ज्ञान, संस्कार एवं सेवा के आधार पर दृढ़ता के साथ देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करने का सन्देश दिया। उद्घाटन समारोह में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डा. सोमनाथ ने अभाविप के थीम सांग को भी जारी किया।

उद्घाटन समारोह के बाद 'युवा भारत का आह्वान-विचार बैठक 2025 के क्रियान्वयन की दिशा' विषय पर अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान का संबोधन हुआ। उसके बाद विस्तार से गटों में चर्चा की गई। रात्रि में हुए अनौपचारिक सत्र में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अधिवेशन के दूसरे दिन प्रा. यशवंत राव केलकर की जीवनी पर आधारित 'यशवंत@100' पुस्तक का विमोचन किया गया एवं 'शिक्षा की भारतीय संकल्पना, वर्तमान परिदृश्य एवं हमारी भूमिका' विषय पर निर्वतमान राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उसके बाद कई समानांतर सत्रों का आयोजन किया गया। साथ ही देहरादून नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधि अपने-अपने पारम्परिक एवं सांस्कृतिक परिधान में उत्साहपूर्वक शामिल हुए। भव्य शोभा यात्रा का स्थानीय नागरिकों ने विभिन्न स्थानों पर फूल-माला के साथ स्वागत किया। स्वागत करने वालों में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सहित कई मंत्री भी शामिल रहे। शोभायात्रा के बाद खुले अधिवेशन में विभिन्न वक्ताओं ने राष्ट्र हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार सामने रखे। रात्रि में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने गीत-संगीत, नृत्य सहित अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से मनमोहक प्रदर्शन करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

तीसरे एवं अंतिम दिन राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर

संघ शताब्दी वर्ष पर समाज परिवर्तन के पंच प्रण का आग्रह

अधिवेशन में संगठन की आगामी योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर हुए विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि छात्रावास सर्वेक्षण अभियान फरवरी माह में एक सप्ताह के लिए चलाया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के छात्रावासों का सर्वेक्षण होगा। महारानी अब्बक्का जन्म के 500वें वर्ष के निमित्त विभिन्न परिसरों में प्रदर्शनी एवं कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्मजयंती पर देशभर के शैक्षिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संघ शताब्दी वर्ष में समाज परिवर्तन के पंच प्रण का आग्रह किया गया है। प्रा. यशवंत राव केलकर जन्मशती वर्ष के निमित्त कार्यकर्ता आग्रह,उद्बोधन एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 350वें गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के निमित्त देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ■

जारी रहेगा 'परिसर चलो अभियान'

शैक्षिक परिसरों में छात्रों की घटती संख्या के समाधान के लिए अभाविप द्वारा चलाया जा रहा 'परिसर चलो अभियान' पूर्ववर्त जारी रहेगा। अभाविप राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने एवं परिसर को जीवंत बनाने में परिषद के इस अभियान को सकारात्मक प्रतिसाद मिला है। इसलिए इस वर्ष भी परिसर चलो अभियान जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि अभाविप के इस अभियान का उद्देश्य परिसरों को जीवंत बनाने एवं परिसर संस्कृति को पुनर्स्थापित करना है। अभियान के माध्यम से छात्रों को परिसर में आने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि वर्ग में विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। ■

धामी युवा पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही शिक्षा, समाज, पर्यावरण, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को प्रदान किए जाने वाला प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार-2025 भी प्रदान किया। वर्ष 2025 का युवा पुरस्कार 'स्माइल रोटी बैंक फाउंडेशन' के अध्यक्ष श्रीकृष्ण पांडेय 'आजाद' को दिया गया। अंतिम दिन राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेन्द्र सोलंकी ने आगामी कार्यक्रमों एवं अभियानों की घोषणा की, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. रघुराज किशोर तिवारी ने नई कार्यकारिणी घोषित की। इससे पूर्व व्यवस्था में लगे कार्यकर्ताओं का परिचय भी कराया गया। अधिवेशन में पांच प्रस्ताव भी पारित हुए। अभाविप राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री गोविंद नायक के समापन भाषण के बाद सायंकाल वंदे-मातरम के गान के साथ ध्वजावतरण हुआ और इसके साथ ही तीन दिन से चल रहे अभाविप के 70 वें अधिवेशन का समापन हो गया। अधिवेशन के दौरान देश के भिन्न-भिन्न राज्यों, विविध संस्कृतियों एवं विविध परम्पराओं से जुड़े अभाविप कार्यकर्ता जिस तरह एक साथ-एक समूह में रहकर सम्पूर्ण आयोजन में सम्मिलित हुए, वह ऐतिहासिक रहा। अधिवेशन में विभिन्न प्रांतों से आए बारह सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मित्र राष्ट्र नेपाल से आए प्रतिनिधि भी शामिल थे। 2026 में तेलगांना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित होने वाले अभाविप के 72वें अधिवेशन में पुनः मिलने की उम्मीद की साथ देहरादून से जब अभाविप के प्रतिनिधियों ने विदाई ली, तो सभी के चेहरों पर संतोष एवं आगामी कार्यों को पूर्ण करने का उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ■

‘ज्ञान, तकनीक और निडर शक्ति से होगा राष्ट्र का उत्थान’

देहरादून में आयोजित अभाविप के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि एवं इसरो के पूर्व अध्यक्ष डा. एस. सोमनाथ के संबोधन के मुख्य अंश

अभाविप के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य शुभारंभ ‘भगवान बिरसा मुंडा नगर’ में बनाए गए ‘जनरल विपिन रावत सभागार’ में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष डा. एस सोमनाथ ने किया। अपने सम्बोधन में मुख्य अतिथि डा. एस. सोमनाथ ने विश्वास और तथ्य को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए कहा कि संस्कृति और नवाचार साथ-साथ कार्य करते हैं। भारतीय ऋषियों ने चेतना, गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, वास्तुकला और चिकित्सा की खोज की। भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों में आधुनिक विज्ञान और उसके रहस्यों की जानकारी को देखा जा सकता है। सारा ज्ञान हमारे अंदर रहता है। भारत की परंपरा कहती है कि ज्ञान पवित्र है और इसे तपस्या (आध्यात्मिक ध्यान) से हासिल किया जाना चाहिए। विज्ञान एक ऐसा साधन है, जिसमें बदलाव लाने की शक्ति है, संस्कार वर्षों और पीढ़ियों की कड़ी मेहनत से बना एक उद्देश्य है और सेवा हर एक का अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य है। जब किसी राष्ट्र के युवा कौशल, साहस और चरित्र के साथ उठ खड़े होते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है।

उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र का उत्थान तभी संभव है, जब उसकी युवा पीढ़ी ज्ञान, तकनीक और निडर शक्ति से सम्पन्न हो। आज के युवाओं को देखकर हर्ष होता है क्योंकि प्रत्येक युवा न केवल वर्तमान का ध्वजवाहक है, बल्कि भविष्य का आधारस्तंभ भी है। यह एक आंदोलन है, एक मिशन है और इसी महत्वपूर्ण परिस्थिति में अभाविप उभरकर सामने आती है। युवा का संकल्प ही राष्ट्र का स्वरूप गढ़ता है। अभाविप ने सदैव भारत की राष्ट्रीय नीतियों को संरक्षित किया है। उसका मार्गदर्शक सिद्धांत ‘चरैवेति-चरैवेति’ उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम एक ऐसी वैश्विक तकनीकी शक्ति हैं, जिसकी सभ्यता अपनी संस्कृति में गहराई से निहित है। भारत की 25 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या युवा है, यह हमारे लिए एक सांस्कृतिक वरदान है। जब युवा दृढ़ होकर खड़े होते हैं, तो

इतिहास की दिशा बदल जाती है। आप वही पीढ़ी हैं, जो भारत का भविष्य लिखेगी। भारत युवाओं से बेहतरीन काम, नेतृत्व एवं चरित्र की उम्मीद करता है। इसलिए बड़े सपने देखें और हिम्मत वाले बनें। भारत एक है और इसको एक रखना युवाओं का दायित्व है।

अभाविप की चर्चा करते हुए डा. सोमनाथ ने कहा कि अभाविप सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, एक मिशन है, एक राष्ट्रीय सोच है जो युवाओं की एक पीढ़ी को उम्मीद देती है। 1949 में जब भारत एक नया स्वतन्त्र देश था, बहुत नाजुक हालात में, अभाविप बड़ी उम्मीद और इस विश्वास के साथ सामने आई कि छात्र सिर्फ कल के नागरिक नहीं हैं, वह आज के नागरिक हैं। यह विश्वास और दिशा देने वाली बन गई, जिसने युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति में बदलने का काम किया। भारत की भविष्य की तकनीकी को आयात नहीं किया जाना चाहिए। इस विषय में हमारे युवा ही सोचेंगे, बनाएंगे और

बेहतर बनाएंगे।

अभाविप कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए डा. सोमनाथ ने कहा कि भारत में एक नया विश्वास बन रहा है। आधुनिक युग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विश्व भारत को एक अलग दृष्टि से देख रहा है। भारत नैतिक स्पष्टता वाला देश हैं। भारत लोकतान्त्रिक स्थायित्व का एक मजबूत स्तम्भ है और यह सरकार में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम एक ऐसी सभ्यता भी हैं जो सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है। यह वह पल है, जिसका हमारे सभी पुरखों ने इंतज़ार किया था। यह वह पल है, जिसके लिए स्वतंत्रता के दीवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी और यह वह पल है जिसका भारत सदियों से इंतजार कर रहा था। आज दुनिया कहती है कि भारत 21वीं सदी में नेतृत्व करेगा और हम जवाब दे रहे हैं कि हां, हमारा समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सच्चा नेतृत्व सेवा में निहित होता है। जब हर हाथ में हुनर होगा, हर मन में विश्वास होगा और हर दिल में भारत होगा, वास्तविकता में वही विकसित भारत होगा। ■

कार्यकर्ताओं की सेवा भावना ने दिलाया संगठन को गौरव : प्रा. तिवारी

अभाविप के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा (डा.) रघुराज किशोर तिवारी ने अपना दायित्व ग्रहण करने के बाद अधिवेशन में आए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि अभाविप विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है, यह गौरव हम सभी को मिला है। जिस विचारधारा के साथ अभाविप काम कर रही है, वह देश को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के दौरान ध्येय यात्रा में कार्यकर्ता-व्यक्ति निर्माण का कार्य छात्र करते हैं। छात्रों को संस्कार देकर देश एवं समाज के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य अभाविप कर रही है। अभाविप की वैज्ञानिक कार्यपद्धति के पीछे भी छात्रों की ऊर्जा है। अभाविप युवाओं को संकल्पित, संस्कारवान और संवेदनशील बनाने का कार्य कर रही है। चंद्रगुप्त–चाणक्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कर्तव्यपथ पर आगे बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रहती है। अभाविप की समाज में स्वीकार्यता बढ़ी है। अभिभावक आज कालेज में प्रवेश के साथ अभाविप कार्यालय का पता पूछते हैं। यह गौरव कार्यकर्ताओं की सेवा भावना ने संगठन को दिलाया है।

उन्होंने कहा कि अभाविप एक संकल्प के रूप में बढ़ रही है। युवा भी संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं। अभाविप समाज के हर हिस्से के लिए काम कर रही है। भारत विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित हो, इसके लिए भी अभाविप काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सौ वर्ष पूरे हो चुके हैं। समाज में संगठन को स्थापित करने का कार्य देश से लेकर विदेश में चल रहा है। पंच परिवर्तन के विषय को बढ़ाने का संकल्प अभाविप ने लिया है।

उन्होंने कहा कि भारत में युवाओं को कर्तव्य पथ पर ले जाने में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, ऐसी ही भूमिका अभाविप के शिल्पकार रहे प्रा यशवंतराव केलकर ने निभाई है। आज अभाविप की स्वीकार्यता समाज में अपनी विशिष्ट और विशेष कार्यपद्धति के चलते बढ़ी है, यह हर्ष का विषय है। आज युवा पीढ़ी के समक्ष हम रोल मॉडल बनके उभरे हैं, अभाविप के कार्यकर्ता इस क्रम में निरन्तर आगे बढ़ते जाएंगे। ■

युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करती है अभाविप : डा. सोलंकी

दायित्व ग्रहण करने के बाद अभाविप के पुनर्निर्वाचित महामंत्री डा. वीरेंद्र सोलंकी ने कहा कि भारतीय एकात्मता के लिए अभाविप कार्यकर्ता निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज 77 वर्षों की अभाविप बहुआयामी वटवृक्ष का रूप ले चुकी है, यह यात्रा इसके पंजीयन 1949 से बहुत वर्ष पहले उन अमर बलिदानियों के ध्येय से शुरू हुई थी, जिन्होंने स्वंतत्रता की लड़ाई में खुद को बलिदान कर दिया था। उसी ध्येय के साथ अभाविप की स्थापना हुई थी, जिसे अभाविप कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि अपने स्थापनाकाल के बाद अभाविप के कार्यकर्ताओं ने समाज को विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने के साथ ही देश के हर एक हिस्से को एकसूत्र में बांधने का काम किया है। आज अभाविप का इतना वृहद स्वरूप हो चुका है कि समाज एवं शिक्षा के सभी विषयों पर अपने आयामों और गतिविधियों के माध्यम से काम किया जा रहा है। आज केवल देश के अंदर ही नहीं अपितु भारत से बाहर पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के बीच भी हम अपने आयाम के माध्यम से 'राष्ट्र प्रथम' के भाव और संकल्प को और मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों से आह्वान करते हुए कहा कि इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन से सीखकर आप अपने कार्यक्षेत्र में जाएं और 'राष्ट्र प्रथम' के भाव को और दृढ़ करने तथा छात्र शक्ति को और गतिमान बनाने का कार्य करें। ■

76 लाख से अधिक हुई अभाविप की सदस्यता

अभाविप के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2024-25 के महामंत्री प्रतिवेदन का सारांश

71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान महामंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अभाविप राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि अभाविप ने अपने पूर्व के सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए नया कीर्तिमान रचा है। 2025 में अभाविप की सदस्य संख्या 76 लाख, 98 हजार 4 सौ 48 हो चुकी है, जो अब तक की अधिकतम संख्या है। पिछले वर्ष की गई सदस्यता में अभाविप ने 59 लाख 36 हज़ार सदस्य बनाए थे, जो इस वर्ष 76,98,448 तक पहुंच चुकी है। प्रतिवेदन में बताया गया कि बाबा साहब भीमराव रामजी आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को अभाविप द्वारा सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 में बाबा साहब के संदेश को याद करते हुए अभाविप के कार्यकर्ताओं द्वारा 3,085 स्थानों में 3,601 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 5,68,439 विद्यार्थियों की सहभागिता हुई। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा पखवाडे के रूप में मनाने वाली अभाविप द्वारा 4821 स्थानों पर 5,989 कार्यक्रम किए गए, जिसमें 12,02,598 युवा सम्मिलित हुए। स्वाधीनता दिवस पर केरल, पश्चिम महाराष्ट्र, असम, उत्तर बंग, मध्य भारत, दक्षिण भारत, हिमाचल प्रदेश, कानपुर, ब्रज, देवगिरि में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कश्मीर स्थित लाल चौक में शान-ए-तिरंगा यात्रा के आयोजन के साथ ही गणतंत्र दिवस पर देश के विविध प्रांतों में ध्वजारोहण एव भारत माता पूजन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इसी प्रकार जनजातीय गौरव दिवस पर अमर जनजातीय क्रांतिनायकों को नमन करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती अर्थात स्त्री शक्ति दिवस पर देश के 3,017 इकाईयों द्वारा 7,193 कार्यक्रम हुए, जिसमें 6,21,019 छात्रों

ने सहभाग लिया। इसी तरह बलिदान दिवस, डा. आंबेडकर जयंती, महिला दिवस, अभियांत्रिकी दिवस पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।

प्रतिवेदन में बताया गया कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में हुए छात्रसंघ चुनावों में अभाविप ने ऐतिहासिक बढ़त हासिल की। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हेमवंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, गौहाटी विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, मंगलौर विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, पटना विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय सहित देश के अनेक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में छात्रों ने लगातार अभाविप के पक्ष में मतदान कर सिद्ध कर दिया कि उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही अभाविप ने देश की राजधानी दिल्ली स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष सहित चार में से तीन पदों पर जीत का परचम लहराकर सिद्ध किया कि परिसर में छात्रों की आवाज अभाविप ही है। सोशल मीडिया मंच पर अभाविप के फॉलोवरों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो फेसबुक पर 5,08,022, एक्स पर 3,30,702, इंस्टाग्राम पर 3,13,338, यूट्यूब पर 44,800, पब्लिक एप्प पर 12 लाख और टेलिग्राम पर 8,044 लोग जुड़े हुए हैं।

लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर मध्यभारत प्रांत में 'इंडिजीनियस' के माध्यम से 'इंडियन इमरजेंसी' कार्यक्रम, पश्चिम महाराष्ट्र में आपातकाल के विरोध को दर्शाने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन, कई प्रांतों में मशाल यात्रा, रैली और जुलूस निकाले गए। ब्रज प्रांत में 'भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय' विषय पर केंद्रित होकर मशाल जुलूस, पुतला दहन, गोष्ठी और पोस्टर के माध्यम से आपातकाल के बारे में जनजागृति का कार्य किया गया।

प्रतिवेदन में अभाविप प्रकल्प 'अंतर-राज्य छात्र जीवन दर्शन' सहित अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी सामने रखी गई। यशवंत शती पर पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश में यशवंत गुणगौरव समारोह एवं दक्षिण तमिलनाडु प्रांत और ओडिशा प्रांत में प्रा. यशवंतराव केलकर जन्म शताब्दी कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ प्रांत में संगोष्ठी, महाकौशल प्रांत में 'प्रिय यशवंत' और 'यशवंत स्मरण' कार्यक्रम, मध्यभारत प्रांत, हरियाणा प्रांत और मालवा प्रांत में 'प्रिय केलकर जी अभिवाचन' कार्यक्रमों का आयोजन, विदर्भ प्रांत में यशवंत विद्यार्थी सत्कार समारोह और कोंकण प्रांत में विद्यार्थी सत्कार समारोह के साथ ही देवगिरी प्रांत में 'यशवंत वारी' और 'सन आर्ट' जैसे रचनात्मक कार्यक्रम हुए, वहीं जोधपुर प्रांत में जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। पंजाब प्रांत में 'हर वृक्ष में केलकर' के नारे के साथ विकासार्थ विद्यार्थी ने विशाल पौधारोपण अभियान चलाया।

लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर मध्यभारत प्रांत में 'इंडिजीनियस' के माध्यम से 'इंडियन इमरजेंसी' कार्यक्रम, पश्चिम महाराष्ट्र में आपातकाल के विरोध को दर्शाने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन, कई प्रांतों में मशाल यात्रा, रैली और जुलूस निकाले गए। ब्रज प्रांत में "भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय" विषय पर केंद्रित संगोष्ठी के साथ ही मशाल जुलूस, पुतला दहन, गोष्ठी और पोस्टर के माध्यम से आपातकाल के बारे में जनजागृति का कार्य किया गया। गोरक्ष प्रांत में "आपातकालीन संघर्ष गाथा" विषय पर संगोष्ठी, पंजाब प्रांत में आपातकाल के वीरों का सम्मान समारोह, मेरठ प्रांत में "आपातकाल निषेध 50 वर्ष निमित्त" कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रतिवेदन के माध्यम से अभाविप के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही आयाम एवं गतिविधि से जुडी महत्वपूर्ण जानकारी को भी सामने रखा गया। ■

'जेन-जी आंदोलन और भारतीय युवा'

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में वैश्विक स्तर पर भिन्न-भिन्न नकारात्मक मांगों को लेकर किए जाने वाले आंदोलन के माध्यम से युवाओं को भ्रमित करने की जारी चेष्टाओं पर विचार रखते हुए अभाविप की केंद्रीय समिति सदस्य डा. निधि बहुगुणा ने समानांतर सत्र में कहा कि वर्तमान समय में तकनीकी विशेषता एवं सिद्धता के कारण सूचना तंत्र में सरलता बढ़ी है। इसका सबसे अधिक लाभ उस जनसंख्या को प्राप्त हुआ है, जो युवा है और जिसे वर्तमान समय में जेन-जी का नाम दिया गया है। जेन-जी में युवाओं की संख्या अधिक है, जिसे सूचना तंत्र के कारण प्रभावित करना आसान हो गया है। वैश्विक स्तर पर जर्मन मार्शल फंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (जेएमएफ), सीएमएफ एवं कट्टरपंथियों का लक्ष्य जेन-जी के बीच अपनी पकड़ को बनाना है। लगभग पचीस वर्षों से ऐसे कई संगठनों ने ऐसे नकारात्मक विमर्श को गढ़ कर जेन-जी तक पहुंच बनाई है, जिसके उदाहरण के रूप में ग्रेटा थनबर्ग एवं मलाला यूसुफजई को देखा जा सकता है। जेन-जी के माध्यम से अपने हितों एवं स्वार्थों को पूरा करने की एक प्रयोगशाला को अमेरिका स्थित बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और उसका भारतीय स्वरूप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि जेएनयू अभी उस स्तर पर नहीं हैं लेकिन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से आरम्भ होने वाले किसी भी प्रयोग का परिणाम अमेरिका के सभी विश्वविद्यालय में फैल जाता हैं। इस प्रयोग से प्रभावित स्वयं को वोक (डब्लूओकेई) कहते हैं और ऐसे नकारात्मक विषयों पर उनका सहयोग वामपंथियों के साथ वह सभी तत्व करते हैं, जिनका लक्ष्य समाज में अस्थिरता फैलाना होता है।

विश्व में सकारात्मक मुद्दों पर होने वाले आंदोलन में जेन-जी के न जुड़ने के कई उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जेन-जी का इस्तेमाल केवल हिंसा के औजार के लिए किया जाता है। युवाओं की भावुकता को प्रयोग करते हुए बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के आन्दोलन को अमेरिका की मीडिया ने जेन-जी आन्दोलन बताया। जेन-जी के नाम पर विश्व के कई देशों में जनमत वाली सरकार को हटाया गया और उनके नेताओं को देश छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसमें एक तथ्य यह भी ध्यान देने लायक है, जो देश अमेरिका के सहयोगी है, वहां ऐसा कोई आन्दोलन नहीं होता है, जिससे जनमत वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जाए। यह सब कई शताब्दियों से जारी है। उन्होंने कहा कि जेन-जी के नाम पर होने वाले आंदोलन स्वतन्त्र रूप से नहीं, बल्कि सुनियोजित रूप से खड़े किए जाते हैं और इनके माध्यम से सिर्फ जेन-जी को ठगा जाता है। इसका उदाहरण बांग्लादेश एवं नेपाल में देखा जा सकता है। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी एवं नेपाल में ईसाई मिशनरियों ने जिस तरह का माहौल बनाया, उसके पीछे धार्मिक कारण भी हैं।

उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार शक्तियों का लक्ष्य युवा ही होते हैं क्योंकि उनके माध्यम से ऐसी शक्तियों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। अपने लाभों एवं हितों के लिए व्यक्तिवाद, परिवार विभाजन, समाज जीवन में विभाजन के लिए यह शक्तियां ऐसे मुद्दे सामने लाती हैं, जिससे युवाओं को उकसाकर आंदोलन के लिए बाध्य किया जाता हैं। भारत में वोक का अधिक प्रभाव नहीं है। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के माध्यम से युवाओं को अचिंतन की अवस्था में डालने के प्रयास हो रहे हैं। इंटरनेट पर कथित रूप से संग्रहित ज्ञान के कारण युवाओं में अचिंतन की अवस्था बढ़ रही है। ऐसे में युवा वैश्विक बाजार शक्तियों एवं वोक जैसे कथित संगठनों के लिए सबसे बड़ा भोजन बन रहे हैं। यह सभी बिना अध्ययन किए अपने विचारों को प्रधान मानते हैं। जेन-जी को हथियार बनाकर नकारात्मक आंदोलन खड़ा करने के प्रयासों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ ही मीडिया के एक वर्ग का भी सहयोग लिया जा रहा हैं।

उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि जेन-जी के नाम पर होने वाले तथाकथित आंदोलन में शामिल होने से पहले युवाओं को इस मुद्दे पर गहनता से विचार करना ही होगा कि कहीं उनके माध्यम से स्वार्थों एवं क्षुद्र हितों को पूरा करने की कुचेष्टा तो नहीं की जा रही है। गहनता से विचार करने के बाद ही सकारात्मक आंदोलन के माध्यम से सकारात्मक समाज और राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया को गति प्राप्त हो सकेगी। ■

‘युवाओं से विकसित भारत का आह्वान’

अभाविप के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान द्वारा दिए गए भाषण के मुख्य अंश

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने देश के सभी प्रांतों से आए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि अभाविप के प्रत्येक वर्ष होने वाले अधिवेशन में अपनी-अपनी इकाईयों, नगरों एवं अपने-अपने परिसरों से कार्यकर्ता सम्मिलित होने के लिए आते है। इस वर्ष भी ऐसा हो रहा है। अभाविप की गतिविधियां एवं कार्यक्रम 1948 में आरम्भ हुए और 1949 में अभाविप का पंजीयन हुआ। उसके बाद तीन दशक तक कार्य करने के बाद 1982 में सिंहावलोकन किया गया। माउंट आबू में हुई पहली विचार बैठक में प्रक्रियाओं के विषय में चर्चा हुई। उसके चार वर्ष पश्चात पुणे में हुई बैठक में आधिकारिक तौर पर सिंहावलोकन किया गया और फिर 1990 में उज्जैन में हुई बैठक में भी पूर्व के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर विचार करने के बाद आगामी रणनीति पर विचार किया गया।

उन्होंने बताया कि 1994 में सारनाथ में हुई विचार बैठक में नब्बे के दशक में हुए उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया और उसके प्रभाव पर विचार किया गया। इसके बाद अभाविप ने एक बड़ा अभियान परिसर संस्कृति के परिवर्तन एवं भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए चलाया। 1998 में हुए 50वें अधिवेशन में जो संकल्प लिया गया था, उस संकल्प को 1999 के अधिवेशन में दोहराया गया। 2003 में शिमला में हुई विचार बैठक में नई सहस्राब्दी पर विचार किया गया। इस विचार बैठक में विदेशों में कार्य, विदेशी विद्यार्थियों के बीच में कार्य, मुस्लिम और ईसाई विद्यार्थियों से सम्पर्क, शिक्षा के व्यापारीकरण पर विचार किया गया। सात वर्ष बाद 2010 में रांची में हुई विचार बैठक में भविष्य के दिशासूत्र पर चर्चा की गई। इसी तरह 2015 में पुष्कर में हुई विचार बैठक में सस्ती, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आग्रह के साथ ही देश के अंदर जो घटनाक्रम बन रहे थे, उसके साथ ही सुरक्षा से जुड़े विषय को सामने रखा गया। 2020 में त्रिची के समीप श्रीरंगम में हुई बैठक में आनंदमय सार्थक छात्र जीवन पर विचार करने के साथ ही अभाविप ने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता का आग्रह भी

रखा। अभाविप का मानना है कि हिंदू जीवन पद्धति, भारत की वास्तविक पहचान, संवैधानिक विमर्श जैसे विषय समाज, विद्यार्थियों एवं युवाओं के सामने लाना ही चाहिए। इसके बाद 2025 में द्वारका में हुई विचार बैठक में गत पांच वर्षों में जो-जो विचार किया था, वह किस तरह प्रतिफलित हुए, इस पर चिंतन किया गया।

उन्होंने कहा कि 2025 में अभाविप की सदस्यता लगभग 78 लाख पहुंच गई है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो अभी लगभग 90 लाख तक पहुंच चुकी होती। अभाविप के कार्य विस्तार को दस हजार स्थानों के साथ ही पचास हजार कालेज तक लेकर जाने का लक्ष्य रखा गया, जिसे 'सेल्फी विद कैंपस' और 'एक गांव-एक तिरंगा अभियान' में फलीभूत होते देखा। आप सभी के लिए संघ शताब्दी वर्ष एक बहुत बड़ा अवसर लेकर सामने आया है। कारण यह है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यह देश पूरी दुनिया के अंदर एक स्थायी सरकार देने में सक्षम है। दुनिया के देशों में नेतृत्व का जो स्थायीपन भारत में है, उतना कहीं और नहीं है। देश के अंदर राजनीतिक क्षेत्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका भाव देश के कल्याण का है।

गत वर्षों में परिसर चलो अभियान का लाभ अभाविप को मिला है। अभियान का स्वागत विद्यार्थियों के साथ ही अध्यापक एवं प्राध्यापक भी कर रहे हैं। आगामी समय में भी यह एक महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है। परिसर में ज्ञान के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ वैविध्यपूर्ण गुणों का सृजन हो, इस दिशा में आनंदमय सार्थक छात्र जीवन का लक्ष्य निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक परिवर्तन और सुधार तेजी से हो रहा है। आज का विद्यार्थी आशावादी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वह स्टार्टअप्स के विषय में विचार करने के साथ ही दुनिया को देश की ताकत दिखाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए वह समाधान निकालने के साथ ही रचनात्मक विचारों से युक्त हैं। युवा भारत के प्रति यह देश का आह्वान है कि वह आने वाले समय में ऐसे किन बिंदुओं पर कार्य करता है, जो देश को आगे लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है। स्कूली क्षेत्र में नई शिक्षा नीति का बहुत अच्छे तरीके से निष्पादन हो रहा है, एनसीआरटी का पाठ्यक्रम बन रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा में निष्पादन की गति धीमी है। इसके लिए राज्यों के सहयोग से गति को बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के हित में जो बिन्दु हैं, उनको लेकर राज्यों की सरकारों के सहयोग के लिए अभियान भी चलाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण औपनिवेशिक मानसिकता को तोड़ने के लिए किया गया है। इसीलिए इसका क्रियान्वयन, उसको धरातल पर लाना और उसके लिए जितने विमर्श गढ़े जा रहे हैं। उनको परास्त करने की दिशा में कार्य करना होगा। शिक्षा की पहुंच सब तक हो, उसके लिए भी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। इसके साथ ही कौशल आधारित शिक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी गति बढ़ानी होगी। अगर कौशल और तकनीकी के क्षेत्र में आने वाले वर्षों में ध्यान दिया गया तो 2047 का भारत, एक विकसित भारत के रूप में सामने होगा।

उन्होंने कहा कि पंच परिवर्तन के साथ ही समरसता के आग्रह के लिए भी बड़े अभियान को चलाने की आवश्यकता है। इस अभियान को बड़े स्वरूप में करते हुए विद्यार्थियों को समाज जागरण के प्रति समाज को, अपने प्रत्येक वर्ग के प्रति एक भाव जागरण का कार्य करना पड़ेगा ताकि भारत का प्रत्येक युवा इस दिशा में आगे बढ़ सके। इसके लिए जनजातीय क्षेत्र हो या अनुसूचित जाति वर्ग हो, समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। पूर्वोत्तर, अंडमान, लक्षद्वीप एवं लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्र में भी यह कार्य करना होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अपने प्रयोग और कार्यों को जब तक समाज के बीच में जाकर नहीं करेंगे, तब तक अभाविप को यश नहीं मिल सकेगा। समाज में भाषाई आधार पर होने वाले द्वंद, क्षेत्रवाद को दूर करने के लिए भारतीय भाषाओं के आग्रह के साथ ही ऐसे नए प्रयोग भी करने होंगे, जिससे देश की सारी भाषाओं के प्रति समाज जागरण हो सके।

आनंदमय सार्थक छात्र जीवन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गत दो वर्षों में परिसर चलो अभियान

का लाभ अभाविप को मिला है। अभियान का स्वागत विद्यार्थियों के साथ ही अध्यापक एवं प्राध्यापक भी कर रहे हैं। आगामी समय में भी यह एक महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है। परिसर में ज्ञान के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ वैविध्यपूर्ण गुणों का सृजन हो, इस दिशा में आनंदमय सार्थक छात्र जीवन का लक्ष्य निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसी तरह गतिविधियों एवं आयाम का कार्य एवं इंटर्नशिप बढ़ती जा रही है। सभी आयामों में आज विद्यार्थियों की सहभागिता कई गुना बढ़ चुकी है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का क्षेत्र नए प्रयोग की दृष्टि से तो बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि इसमें भी नैतिकता का प्रयोग होना चाहिए। नकल की दृष्टि से इस दिशा में सजगता बढ़ानी होगी।

अभाविप प्रत्येक पांच और दस वर्षों में एक पीढ़ी को दिशा देने का कार्य करती रही है। अब यह भी विचार करना होगा कि अभाविप के प्रांतों में कौन से ऐसे मुद्दे है जो पीढ़ी की भावना (जेनरेशनल स्पिरिट) खड़ी करेंगे? आने वाला समय सुरक्षा, सामाजिक शिक्षा, अपने परिवेश और अर्थ जगत के अंदर इन सभी विषयों को साथ लेने वाला बनेगा।

सीखने के लिए एआई का प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए युवाओं को जागृत करना होगा। आगामी समय में अभाविप इस दिशा में कार्यशालाओं का आयोजन करेगी, ताकि युवाओं में सकारात्मक रूप से एआई का उपयोग करने की प्रवृत्ति बन सके। उन्होंने कहा कि भारत की परिवार परम्पराएं, संस्कार, जिनको दसियों-हजार वर्षों से जिया है, उसमें एक प्राकृतिक रूप से सीखने की प्रक्रिया समाहित है और इसे समाप्त करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि देश ने संविधान का 75वां वर्ष मनाया है। मूल संविधान में सोशलिस्ट और सेक्यूलर शब्द नहीं था, लेकिन आपातकाल के समय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दोनों शब्द को जबरदस्ती शामिल कर दिया। ऐसे में परिसरों में मूल संविधान को लेकर चर्चा करने के साथ ही यह विचार करना होगा कि संविधान क्यों बदला गया? पंच परिवर्तन के माध्यम से व्यक्ति निर्माण पर भी चर्चा एवं विमर्श की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण के प्रयोग स्वयं से लेकर परिसर, गांव, घर और पड़ोस में करने होंगे। साथ ही समाज में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी विचार करने की भी प्रबल आवश्यकता है क्योंकि नशा बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है। इसके विरुद्ध छेड़ी जाने वाली लड़ाई में हर वह व्यक्ति सम्मिलित होगा जो नशे की लत से बचना चाहता है और उसके लिए प्रयासरत हैं। आगामी समय में नए प्रयोग करने होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित करके समाज कार्य को आगे ले जाने का कार्य किया जा सकेगा।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी को देश की सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर भी विचार करना चाहिए। कश्मीर, केरल, बिहार से लेकर उत्तर-पूर्व के चिकेननेक वाले क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठ सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर विषय है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर पुनः चर्चा करने की आवश्यकता है। इसी तरह माओवादी जो जंगल में समाप्त हो रहे हैं, वह अब नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस गंभीर विषय पर भी विचार-विमर्श को बढ़ाना होगा। सभी को यह बात सजगता से समझनी होगी कि प्रत्येक पीढ़ी के सामने एक राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए। कारण यह है कि प्रत्येक पीढ़ी के सामने एक स्मृति रहनी चाहिए क्योंकि वही स्मृति उस पीढ़ी को परिभाषित करती है। आगामी पीढ़ी कौन से आंदोलन की बात करेगी? इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा।

उन्होंने कहा कि अभाविप प्रत्येक पांच और दस वर्षों में एक पीढ़ी को दिशा देने का कार्य करती रही है। अब यह भी विचार करना होगा कि अभाविप के प्रांतों में कौन से ऐसे मुद्दे है जो पीढ़ी की भावना (जेनरेशनल स्पिरिट) उत्पन्न करेंगे? आने वाला समय सुरक्षा, सामाजिक शिक्षा, अपने परिवेश और अर्थ जगत के अंदर इन सभी विषयों को साथ लेने वाला बनेगा। विचार बैठक के बिंदु सभी के सामने है और जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, आगामी वर्षों में उन बिंदुओं को लेकर अभाविप आप सभी से समाज और युवाओं के बीच में जाने का आह्वान करती है। ■

‘ज्ञान आधारित भारतीय शिक्षा परंपरा पर होना चाहिए विचार’

अभाविप के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही द्वारा दिए गए भाषण के मुख्य अंश

भारत में शिक्षा की पूरी परंपरा धर्म आधारित, कर्तव्य आधारित और मनुष्यता आधारित परंपरा है। शिक्षा की यह प्रक्रिया कर्तव्यबोध को प्रेरित करती है। लेकिन भारतीय शिक्षा को इस परंपरा से काटने का प्रयास किया गया। आज शिक्षा की जड़ें लोक परंपरा में नहीं है। इसीलिए शिक्षित व्यक्ति को अपनी संस्कृति से काटा जा रहा है। स्थानीय, क्षेत्रीय, भाषाई तथा राज्य संबंधी निष्ठाओं के कारण लोग भारत को भूलते जा रहे हैं। वह पुराने भारतीय मूल्य, जो समाज को जोड़कर रखते थे, आज वह मूल्य दिखाई नहीं देते। सामाजिक अव्यवस्था के असंख्य संकेत प्रत्येक क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में युवा पीढ़ी के अंदर सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित करने के लिए किसी प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता है। देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए यह विचार निवर्तमान अध्यक्ष डा. राजशरण शाही ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के राष्ट्रीय अधिवेशन में आयोजित भाषण सत्र में सामने रखे।

उत्तराखंड की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह पावन भूमि गंगा और यमुना का ही उद्गम स्थल नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की गंगा की भी प्रवाह भूमि है। सनातन संस्कृति की दो परम्पराएं परा और अपरा विद्या, दोनों की समानांतर धाराएं यहां से बहुत ही प्रखरता के साथ निकलती हैं। इसलिए भारत की शिक्षा की संकल्पना के लिए इस भूमि से उपयुक्त स्थान और कोई नहीं हो सकता। भारत की गुरुकुल

की जो श्रेष्ठ परंपरा थी, उसी ने भारत को विश्व गुरु बनाया। भारत को विश्वगुरु बनाने का जो कारखाना था, वह गुरुकुल था। गुरुकुल की श्रेष्ठ परंपरा के प्रतिमान के रूप में भी गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम भी इसी भूमि पर था। इन सारी दृष्टियों से जब विचार किया जाता है तो शिक्षा की भारतीय संकल्पना पर विचार के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थल प्रतीत होता है।

उन्होंने कहा कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है, वह जिज्ञासा को जागृत करने की परंपरा है। शिक्षा के माध्यम से सभी प्रकार की विषमताओं को दूर करने की परंपरा देश में रही है। शिक्षा टुकड़ों में बांटने या विभेद उत्पन्न करने के स्थान पर विषमताओं को समाप्त करते हुए एकात्मता का भाव जागृत करने की परंपरा है। भारतीय शिक्षा परंपरा स्वतः जानने की केवल परंपरा नहीं है, बल्कि जो कुछ भी जाना है, वह सर्व समाज को समर्पित करने का भाव है। भारतीय शिक्षा का अर्थ ज्ञान का प्रयोग जीवन में हो और उसका प्रसार सर्व समाज तक हो। इसीलिए भारत में कहा गया है कि "वादे-वादे जायते तत्वबोधः"। तत्वबोध की परंपरा, चिंतन की, परम्परावाद की, संवाद की और संवाद के माध्यम से श्रेष्ठता की ओर ले जाने की परंपरा है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य का यह संकट है कि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन हो गया है, जहां विषयों की शिक्षा दी जाती है। प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि विश्वविद्यालयों को मानवता के उत्कृष्ट केंद्र, सृजनात्मकता केंद्र और रचनात्मक केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए, जहां विद्यार्थी को रूढ़िगत विचारों और भावों से मुक्त करके उनकी आध्यात्मिक चेतना का विकास होना चाहिए।

डा. शाही के अनुसार भारतीय शिक्षा परंपरा केवल सूचना की परंपरा नहीं है, बल्कि परिवर्तन की परंपरा है। शिक्षा का उद्देश्य पीछे चलना नहीं है, बल्कि नेतृत्व के विचार के साथ समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करना है। आध्यात्मिक चेतना के जागरण के केंद्र शिक्षालय होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को धर्म से काटने का प्रयास किया गया। धर्म के दस तत्व से जब मनुष्य कटेगा तो जीवन और समाज कहां जाएगा? इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से भारत की शिक्षा को भारत की ज्ञान परंपरा से, भारत की शिक्षा से, भारत की संस्कृति से, भारत की प्रकृति से, जोड़ने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। किसी भी शिक्षा का उसकी संस्कृति से जोड़ना कितना महत्वपूर्ण होता है? शिक्षा की इस परम्परा को समझना होगा। भारत की शिक्षा परंपरा ने सदैव संस्कार एवं मूल्य देने का काम किया है। इसीलिए भारत की ज्ञान परंपरा और भारत की भाषा को भारत की शिक्षा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

21वीं सदी में शिक्षा की चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की परीक्षा प्रणाली में जब तक आमूलचूल बदलाव नहीं होगा, तब तक यह रोग से मुक्त नहीं होगी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली ऐसी हैं

भारत की परीक्षा प्रणाली में जब तक आमूलचूल बदलाव नहीं होगा, तब तक यह रोग से मुक्त नहीं होगी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली ऐसी हैं जो छात्र के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न कर रही है, जबकि यह सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। भारत की शिक्षा परंपरा संस्कार, लोक कल्याण, त्याग की परंपरा से ओत-प्रोत रही है ।

जो छात्र के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न कर रही है, जबकि यह सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। भारत की शिक्षा परंपरा संस्कार, लोक कल्याण, त्याग की परंपरा से ओत-प्रोत रही है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में परीक्षा में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा केवल व्यक्ति के विकास एवं केवल सामाजिक उन्नयन के लिए ही नहीं, बल्कि वह वसुधैव कुटुम्बकम् या विश्व कल्याण के विभिन्न भाव को जागृत करती है। इसलिए भारत में भारतीयता आधारित शिक्षा की दिशा में अभाविप के युवा अपनी रचनात्मक और प्रभावी भूमिका का निर्माण करेंगे, तभी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के स्वप्न को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। ■

‘राष्ट्रभाव से एकत्व के लिए कार्य कर रही है अभाविप’

अभाविप के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान आयोजित प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह को मुख्य अतिथि एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। उनके संबोधन के प्रमुख अंश

उत्तराखंड राज्य की स्थापना के पच्चीस वर्ष पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) कार्यकर्ताओं का 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वागत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभाविप के संकल्प, विचार एवं कार्यों को देश के विकास में मील के पत्थर की संज्ञा दी। अधिवेशन में आयोजित प्रा. यशवंतराव केलकर पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि धामी ने गोरखपुर निवासी श्रीकृष्ण पांडेय ‘आजाद’ को यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया।

पुरस्कार प्रदान करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं को राष्ट्रीय विकास की ओर अग्रसर करने और उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा देने के लिए अभाविप की प्रशंसा करते हुए राज्य में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन को “राष्ट्र निर्माण का एक पवित्र यज्ञ” बताया। उन्होंने कहा कि विचारों की एकता, राष्ट्रभाव की शक्ति से सभी को एक सूत्र में पिरोकर रखने का काम अभाविप ही कर रही है।

उन्होंने कहा कि यह वर्ष मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष है और संघ ने 100 वर्षों की तपोमय यात्रा के माध्यम से देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक समरसता, राष्ट्र गौरव और राष्ट्र सेवा की ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित की है, जिसने देश के कोने-कोने में राष्ट्रीय चेतना की अखंड ज्योति को प्रज्ज्वलित करने का काम किया है। संघ की दिव्य धारा से ही 1949 में अभाविप का निर्माण हुआ। वह वह समय था, जब देश एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। प्रा. केलकर ने ज्ञान, शील,

एकता के त्रिदेव सिद्धांत को अपनाकर अभाविप को एक संगठित राष्ट्रवादी, चरित्रवान, छात्र शक्ति के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय लगाया गया एक छोटा सा पौधा, आज दुनिया में विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन बन गया है।

उन्होंने कहा कि अभाविप ने पिछले सात दशक में राष्ट्रनिर्माण का कार्य अनवरत रूप से आगे बढ़ाया है और अभाविप केवल छात्र मुद्दों तक ही सीमित नहीं है। देश और समाज के सामने आने वाली हर चुनौती को अपनी चुनौती मानकर मैदान में उतरकर अभाविप ने उन चुनौतियों का सामना किया है। आज भारत की युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है और यह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपनी प्रतिभा, संकल्प के बल पर सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। देश की युवा ऊर्जा को सही मार्गदर्शन दिया जाए, तो देश न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि फिर से सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बन जाएगा। ■

'प्रा. केलकर के मंत्रों से अभाविप बना विश्व का सबसे बड़ा संगठन'

प्रा. यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार से सम्मानित स्माइल रोटी बैंक फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीकृष्ण पांडेय 'आजाद' को बधाई देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. छगनभाई नानजीभाई पटेल ने कहा कि अभाविप के शिल्पकार प्रा.केलकर के जीवन का उद्देश्य समाज में मूल्य और चरित्र का निर्माण करना रहा। उनकी मेहनत एवं क्षमताओं के कारण वर्तमान में अभाविप विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बन गया है। टीम वर्क, चरित्र, राष्ट्रभक्ति और सभी से जुड़ने के लिए उन्होंने जो रचना दी, उसी रचना के आधार पर अभाविप बढ़ती जा रही है। संस्कृति के साथ संघर्ष, विवेक के साथ विरोध और स्वयं को पीछे रखकर नेतृत्व करने का विचार मंत्र उन्होंने ही दिया। सामूहिकता, पारस्परिकता, अनामिकता, अनौपचारिकता का मंत्र लेकर अभाविप कार्यकर्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं।

प्रा. केलकर के जीवन से जुड़े कई प्रसंगों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि समाज का कोई भी व्यक्ति जब उनसे मिलता था, तो उनका भाव सभी को जोड़ने वाला ही रहता था। समरसता से जुड़े कई उदाहरण उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। अभाविप में छात्रा कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं का सहभाग बढ़ाने पर भी उन्होंने ध्यान दिया। अभाविप के आयाम एवं गतिविधियों के साथ ही सील प्रोजेक्ट जैसे रचनात्मक कार्यक्रम का आरम्भ होने में उनकी भूमिका रही। युवाओं के मन में आने वाले जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर वह इस तरह देते थे, जिससे सभी का मन शांत हो जाता था। वह आंदोलन के वास्तुकार भी थे और ऐसा गुणसंपन्न कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। उनके स्मरण वाली प्रसिद्ध पुस्तक पूर्णांक की ओर का अध्ययन सभी को करना चाहिए। आज वह दुनिया में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वह आज भी हमारे साथ हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। ■

Delhi Tourism

दिल्ली

इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्वितीय सम्मिश्रण

भारत का हृदय, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ अतीत और वर्तमान न केवल मिलते हैं, बल्कि एक-दूसरे में सहजता से घुल-मिल जाते हैं। यह राजधानी सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अविस्मरणीय अनुभवों का खजाना है। चाहे आप सदियों पुराने स्थापत्य कला के अजूबे देखना चाहते हों, लज़ीज़ स्ट्रीट फ़ूड का स्वाद लेना चाहते हों, या जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य में गोता लगाना चाहते हों, दिल्ली हर बार आपको विस्मित करती है।

इस अद्वितीय अनुभव को और सुलभ, आकर्षक और आनंददायक बनाने के लिए, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड (DTTDC) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपने चुनिंदा कार्यक्रमों, अनोखे दर्शनीय स्थलों की यात्रा और नए यात्रा पैकेजों के माध्यम से, दिल्ली पर्यटन यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय लोग और पर्यटक, दोनों ही इस शहर का ऐसा अनुभव प्राप्त करें जैसा पहले कभी नहीं किया हो। आइए, दिल्ली पर्यटन के साथ दिल्ली की जीवंत सड़कों की यात्रा करें और इसके कई अजूबों को करीब से देखें।

दिल्ली हाट: संस्कृति और शिल्प का उत्सव

दिल्ली पर्यटन की सबसे पसंदीदा पहलों में से एक है दिल्ली हाट—एक ओपन-एयर बाज़ार जो वास्तव में संस्कृति और शिल्प का उत्सव है। यह पूरे भारत के कारीगरों, शिल्पकारों और खाद्य विक्रेताओं को एक छत के नीचे लाता है। आई.एन.ए, पीतमपुरा और जनकपुरी में स्थित, ये तीन हाट देश की विविध विरासत की एक प्रामाणिक झलक पेश करते हैं। शिल्प, व्यंजन और संस्कृति के तीन स्तंभों पर आधारित, दिल्ली हाट सिर्फ़ एक खरीदारी स्थल नहीं है; यह एक ऐसा मंच है जहाँ पारंपरिक कारीगर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं, खाने के शौकीन क्षेत्रीय व्यंजनों का आनंद लेते हैं, और सांस्कृतिक प्रदर्शन वातावरण में जीवंतता भर देते हैं।

दिल्ली सिर्फ अपने बाजारों के लिए ही नहीं, बल्कि चिंतन और श्रद्धा के स्थानों के लिए भी जानी जाती है।

गुरु तेग बहादुर मेमोरियल

अपने आकर्षक 24 मीटर ऊँचे स्तंभ के साथ, पूज्य सिख गुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। यह स्थल गुरु तेग बहादुर के बलिदान और शिक्षाओं का सम्मान करते हुए एक गहरा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है।

दिल्ली फिल्म नीति 2022: फिल्म निर्माताओं के लिए एक नया युग

दिल्ली सिर्फ अतीत में ही नहीं जी रही, बल्कि भविष्य की ओर भी देख रही है। दिल्ली फिल्म नीति 2022 अपनी समृद्ध विरासत और आधुनिक क्षितिज के साथ दिल्ली को एक प्रमुख फिल्मांकन स्थल के रूप में वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए तैयार है। यह नीति ई-फिल्म क्लीयरेंस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में फिल्म शूटिंग की अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाती है और सब्सिडी जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह न केवल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करती है, बल्कि स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देती है और मनोरंजन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करती है।

गार्डन ऑफ फाईव सेंसेस: शहर में एक शांत विश्राम स्थल

दिल्ली के कई हरे-भरे स्थानों में, गार्डन ऑफ फाईव सेंसेस एक अच्छा रमणीय स्थल है। दक्षिण दिल्ली में स्थित, यह खूबसूरत लैंडस्केप वाला पार्क सभी पाँच इंद्रियों—दृष्टि, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श और गंध—को सक्रिय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस बगीचे में मूर्तियाँ, फव्वारे, हरी-भरी हरियाली और जीवंत फूलों की क्यारियाँ हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाती हैं। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला प्रतिष्ठान और खाद्य उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं, जो प्रकृति और रचनात्मकता का एक आदर्श सम्मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली के अन्य प्रसिद्ध पार्कों में लोधी गार्डन, मुगल गार्डन और नेहरू पार्क शामिल हैं, जो शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से परे एक ताज़गी भरा अनुभव प्रदान करते हैं।

आज़ाद हिंद ग्राम और कॉफ़ी होम: इतिहास और आतिथ्य का एक सम्मिश्रण

इतिहास प्रेमियों के लिए, टिकरी कलां में आज़ाद हिंद ग्राम ज़रूर जाना चाहिए। यह संग्रहालय और स्मारक परिसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का स्मरण कराता है। यह भारत के सबसे प्रभावशाली एक नेता के जीवन और संघर्षों की एक गहन यात्रा प्रदर्शित करता है।

दूसरी ओर, कनॉट प्लेस स्थित कॉफ़ी होम एक आरामदायक जगह है जहाँ पर्यटक स्वादिष्ट और किफ़ायती दक्षिण भारतीय व्यंजनों का आनंद ले

सकते हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के बीच यह एक पसंदीदा जगह है, जहाँ आप आराम कर सकते हैं और शहर के कुछ बेहतरीन फ़िल्टर कॉफ़ी और डोसा का स्वाद चख सकते हैं।

देखो मेरी दिल्ली ऐप: आपका निजी डिजिटल टूर गाइड

आज की डिजिटल दुनिया में, दिल्ली पर्यटन ने एक अभिनव कदम उठाया है: 'देखो मेरी दिल्ली' मोबाइल ऐप। यह ऐप पर्यटन से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करता है। स्मारकों, बाज़ारों, भोजनालयों और मनोरंजन केंद्रों की जानकारी के साथ-साथ, यह ऐप Google Maps एकीकरण के साथ आधे दिन के दौरे से लेकर छह दिन के यात्रा कार्यक्रम तक के लिए ख़ास सुझाव प्रदान करता है। इसकी अनूठी विशेषता उपयोगकर्ताओं को 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जगहों को खोजने की सुविधा देती है, जो इसे आपका निजी, पॉकेट-साइज़ टूर गाइड बनाती है।

डॉ॰ कलाम मेमोरियल

दिल्ली में कई ऐसे स्थल हैं जो भारत के महान नेताओं को श्रद्धांजलि देते हैं। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को समर्पित डॉक्टर कलाम मेमोरियल, उनकी व्यक्तिगत कलाकृतियों और विज्ञान एवं समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान को दर्शाने वाली एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी प्रदर्शित करता है। कलाम मेमोरियल युवाओ के लिए एक प्रेरणा है, जो भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक के जीवन की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

दिल्ली में त्यौहार और सांस्कृतिक समारोह

दिल्ली अपनी जीवंत विरासत का जश्न मनाने वाले मेलों और त्यौहारों से जीवंत हो उठती है।

दिल्ली पर्यटन (डीटीटीडीसी) विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिनमें गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल और फूड फेस्टिवल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक मनोरंजन, परंपरा और लजीज व्यंजनों का अनूठा सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। ये त्यौहार पूरे भारत और विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे ये दिल्ली के सांस्कृतिक कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण आकर्षण बन जाते हैं।

छिपी हुई ऐतिहासिक विरासते : अनदेखी दिल्ली

अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के अलावा, दिल्ली में कई अनछुए अजूबे, पर्यटन स्थल छिपे हैं जिन्हें खोजना ज़रूरी है। इनमें से कुछ हैं:

- **मोठ की मस्जिद –** 15वीं शताब्दी की एक अद्भुत मस्जिद जिसमें जटिल नक्काशी है।
- **मिर्ज़ा ग़ालिब की हवेली –** भारत के महानतम उर्दू कवि का पूर्व निवास।
- **चोर मीनार –** एक रहस्यमयी मध्ययुगीन मीनार जिसका अतीत भयावह है।
- **ईसा खान का मकबरा –** मुगल काल का एक कम प्रसिद्ध वास्तुशिल्प आश्चर्य का केंद्र ।
- **अग्रसेन की बावली –** मंत्रमुग्ध कर देने वाले वातावरण वाली एक ऐतिहासिक बावली।
- **बिजय मंडल किला –** एक छिपा हुआ रत्न जो मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है।

विरासत और हेरिटेज / हाउंटेड वॉक के ज़रिए दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की सैर

दिल्ली के इतिहास से जोंडने का एक बेहतरीन तरीका दिल्ली पर्यटन की हेरिटेज वॉक्स में शामिल होना है। ये हेरिटेज वॉक्स पर्यटकों को चांदनी चौक, महरौली पुरातत्व पार्क, हौज़ खास, कर्तव्यपथ जैसे कुछ सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराती हैं, जहाँ अतीत की दिलचस्प कहानियाँ और छिपे हुए रहस्य उजागर होते हैं। मालचा महल और फिरोज शाह कोटला में हाउंटेड वॉक, जहाँ की कहानियाँ, इतिहासकारों के और स्टोरीटेलर के व्याख्यान से जीवंत हो उठती हैं।

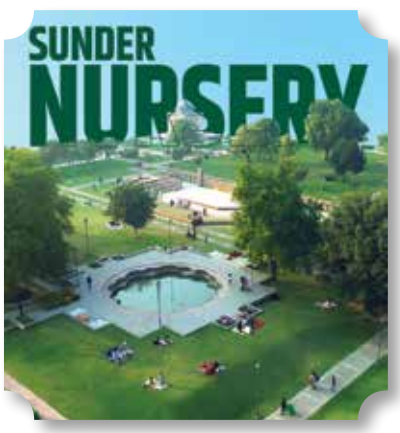

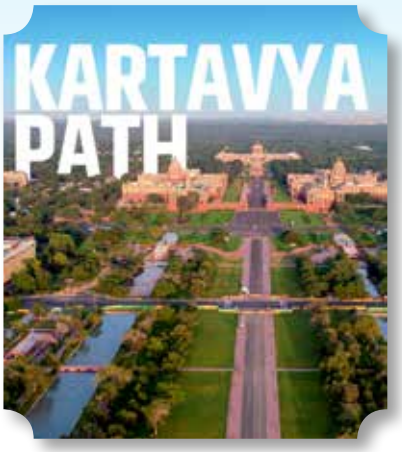

दिल्ली पर्यटन द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए कई टूर्स भी प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

- **दिल्ली** के दर्शनीय स्थलों की यात्रा।
- एक ही दिन में आगरा **(ताजमहल और आगरा किला) की यात्रा।**
- 3-दिवसीय **आगरा-जयपुर यात्रा।**
- 2-दिवसीय **हरिद्वार-ऋषिकेश यात्रा।**
- 2-दिवसीय **मथुरा-वृंदावन-आगरा फतेहपुर सीकरी यात्रा।**

दिल्ली पर्यटन के साथ अपनी यात्रा की योजना बनाएँ और आनंददायी अनुभव प्राप्त करें;

बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए, दिल्ली पर्यटन के केंद्रीय आरक्षण कार्यालय से संपर्क करें:

011-23363607 / 011-23365358
tourism@delhitourism.gov.in
www.delhitourism.gov.in
delhitourism
delhitourism_official
dttdcnews
dttdcnews

चाहे आप पहली बार आए हों या अनुभवी यात्री हों, दिल्ली खुली बाहों और अनंत संभावनाओं के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप हमे सेवा का अवसर दें ।

प्रदर्शनी ने कराया रानी अब्बक्का के तेज और शौर्य से परिचित : आचार्य बालकृष्ण

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद समारोह के मुख्य अतिथि एवं पतंजलि योग ट्रस्ट के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि मां भारती की आराधना में रत रहने वाले अभाविप के कार्यकर्ता अपने आचरण एवं जीवन मूल्यों से दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। अभाविप का राष्ट्रीय अधिवेशन पहली बार उत्तराखण्ड में हो रहा है। इस बात की प्रसन्नता जितनी है, उससे अधिक आनंद आप सभी की उत्साहपूर्ण उपस्थिति से हो रहा है। अभाविप जैसे संगठन से जुड़ना पुण्य और गौरव का विषय है। अपने आचरण और जीवन-मूल्यों से अभाविप के कार्यकर्ता दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। रानी अब्बक्का की यह भव्य प्रदर्शनी उनके तेज और शौर्य को सामने रखती है। साथ ही, उत्तराखण्ड की विशिष्ट परंपरा को विद्यार्थियों द्वारा जिस सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है, वह अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि 'राष्ट्र प्रथम' हम सभी का मूल मंत्र है और हम सब उसी प्राचीन गुरुकुल परंपरा के वाहक हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरण के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे हम सभी को अवश्य जुड़ना चाहिए।

छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती है अभाविप : धन सिंह रावत

रानी अब्बक्का प्रदर्शनी के उद्घाटनकर्ता तथा उत्तराखण्ड सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि जब वह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, उस समय मन में यह इच्छा रहती थी कि राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तराखण्ड में भी आयोजित हो। यह पहली बार हो रहा है कि अभाविप ने उत्तराखण्ड में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया है। अभाविप कार्यकर्ता वर्ष में 365 दिन निरंतर कार्य करते हैं। यह भी अत्यंत गर्व का विषय है कि अभाविप कार्यकर्ताओं में से वर्तमान समय में देश के विभिन्न राज्यों में 8 शिक्षा मंत्री कार्यरत हैं। उन्होंने छात्र एवं छात्राओं से अभाविप संगठन से जुड़ने का आह्वान भी किया। ■

रानी अब्बक्का प्रदर्शनी देखकर अभिभूत हुए दर्शक

71 वें अधिवेशन में "रानी अब्बक्का प्रदर्शनी" सभी के आकर्षण का केंद्र रही। प्रदर्शनी का विषय "देवभूमि से राष्ट्रभूमि तक-उत्तराखण्ड के 25 वर्षों की यात्रा एवं विजन-2047 के संदर्भ में राष्ट्रीय पुनर्जागरण" रहा। भव्य प्रदर्शनी में अभाविप के विचार-वृक्ष, संगठन के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अभियान, छात्रसंघ चुनावों में संगठन की भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की विभूतियां जैसे विषयों को प्रमुखता से दर्शाया गया। प्रदर्शनी में रानी अब्बक्का को भारतीय अस्मिता, स्त्री-शौर्य और राष्ट्र-निष्ठा के सर्वोच्च प्रतीकों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रदर्शनी में उत्तराखंड के वीर योद्धाओं तीलू रौतेली, माधव सिंह भंडारी और अन्य स्थानीय नायकों की गाथाओं को भी विशिष्ट स्थान दिया गया। राज्य की आध्यात्मिक विरासत, पर्वतीय जीवनशैली, पारंपरिक घरों के जीवन-आकार मॉडल, आभूषणों, कृषि उपकरणों और पहाड़ी वास्तुकला की झलकियां आगंतुकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ती दिखाई दी। राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों, मंदिरों, पौराणिक स्थानों, त्यौहारों और लोकनृत्यों के साथ-साथ नंदा राजजात यात्रा, जागर परंपरा और विभिन्न स्थानीय देवताओं की सांस्कृतिक उपस्थिति का आकर्षक प्रदर्शन भी प्रदर्शनी में किया गया। प्रदर्शनी में आदिगुरु शंकराचार्य, गौरा देवी, स्वामी रामतीर्थ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, माधो सिंह भंडारी, गोविंद बल्लभ पंत और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित विशिष्ट मंडप भी स्थापित किए गए। समग्रतः रानी अबक्का प्रदर्शनी में न केवल अभाविप के विचार, कार्य, इतिहास और संगठनात्मक विस्तार का जीवंत प्रस्तुतीकरण किया, बल्कि रानी अब्बक्का जैसी अपराजेय नायिका के योगदान को राष्ट्रीय विमर्श में पुनःस्थापित किया। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, पंच परिवर्तन, 1975 का आपातकाल, संविधान की 75वीं वर्षगांठ, वंदे मातरम के 150 वर्ष, ऑपरेशन सिंदूर, बारदोली सत्याग्रह, प्रा. यशवंतराव केलकर शती, बिरसा मुंडा, भूपेन हजारिका सहित देश के महानायक एवं स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष रूप से उकेरा गया। ■

भारत का बदलता सुरक्षा परिदृश्य

राष्ट्रीय अधिवेशन में समानांतर सत्र के दौरान उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्विनी शर्मा ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के नवाचार, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभावी कार्यान्वयन, सैन्य दूरदर्शिता और राष्ट्रवादी नेतृत्व के सम्मिश्रण ने देश को न केवल अपने लोगों और भू-भाग की रक्षा करने में सक्षम बनाया है, बल्कि 21वीं सदी में एक उच्च तकनीक वाली सैन्य शक्ति के रूप में अपनी भूमिका भी स्थापित की है।

आपरेशन सिंदूर से लेकर आपरेशन महादेव तक की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह आपरेशन भारतीय अस्मिता, राष्ट्रीय स्वाभिमान और निर्णायक नेतृत्व के प्रतिमान बनकर उभरे हैं। 'सिंदूर' जहां भारत की अस्मिता, दृढ़ इच्छाशक्ति और बदलते सामरिक दृष्टिकोण का प्रतीक है, वहीं 'महादेव' अर्थात शिव-भारतीय चेतना, आस्था और जन-मानस के अदम्य साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह दोनों नाम मात्र सैन्य अभियानों के औपचारिक शीर्षक नहीं रहे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक जड़ों और राष्ट्रीय आत्मगौरव की स्वीकार्यता को नए स्वरूप में प्रस्तुत करने वाले शक्तिशाली प्रतीक बने।

उन्होंने कहा कि गत 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। यह हमला भारत में न केवल सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का एक प्रयास था, बल्कि भारत की संप्रभुता के ऊपर हमला था। भारत ने हमले में शामिल पाकिस्तान के दोषी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए आपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान ने भारतीय धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और गोलाबारी का इस्तेमाल किया। लेकिन भारत ने अपने युद्ध कौशल एवं कूटनीति से इन सभी हमलों का सही और सटीक उत्तर दिया।

आपरेशन सिंदूर को मात्र सामरिक सफलता न बताते हुए उन्होंने कहा कि आपरेशन सिंदूर की सफलता भारत की रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण नीतियों का प्रमाण है। इस आपरेशन ने दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक और सामरिक परिदृश्य को एक नया आकार दिया है। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, संकल्प और वैश्विक प्रतिष्ठा की वैश्विक स्वीकारोक्ति है।

उन्होंने कहा कि आपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि यह एक सफल असैन्य अभियान भी रहा, जो भारत की कूटनीतिक सफलता का परिणाम था। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को समाप्त करना, अटारी-वाघा सीमा को बंद कर द्विपक्षीय व्यापार निलंबित करना, पाकिस्तानियों के वीज़ा रद्द करना, पाकिस्तानी कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को उजागर करना आदि कदम भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा रहे। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के प्रतिनिधियों ने आपरेशन सिंदूर की सफलता को आतंकवाद के विरुद्ध कठोर और निर्णायक कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने भारत की कूटनीतिक स्थिति को और सुदृढ़ बनाते हुए पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया।

उन्होंने कहा कि आपरेशन सिंदूर सैन्य और असैन्य (कूटनीतिक) रूप से तो लड़ा ही गया, लेकिन यह आपरेशन भारत में आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त जन आंदोलन के रूप में भी दिखाई दिया। देश के नागरिकों ने न केवल सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मॉक ड्रिल मे भाग लिया, अपितु तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सैन्य बलों का मनोबल बढ़ाया। देश के बदलते सुरक्षा परिदृश्य के परीक्षण ही नहीं, बल्कि उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर को सदियों तक याद रखा जाएगा। भारत ने न केवल डिजिटल सतर्कता प्रदर्शित की, बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के स्थान पर अत्यंत संतुलित दृष्टिकोण भी अपनाया गया। यह सफलता राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार की रक्षा मामलों में सक्रियता एवं दूरगामी चिंतन का प्रभाव भी है। ■

'संतुलित और संस्कारित जनसंख्या भी होना चाहिए विकसित भारत का लक्ष्य'

राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए समानांतर सत्र के दौरान अभाविप पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही ने सामाजिक समरसता और आंतरिक स्थिरता, आर्थिक एवं मानव संसाधन के पुनर्संतुलन, नगरीकरण और बुनियादी ढांचे का भार, नीति-निर्माण एवं मानव पूंजी निर्माण की दिशा में जनसंख्या असंतुलन को एक बड़ी बाधा करार दिया। अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में जनसंख्या असंतुलन के कारण नीतियों का निर्माण सही रूप से नहीं हो पाता है। जब कुछ धर्मों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक हो, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन वितरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संतुलन बनाना एक चुनौती बन जाता है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक और मानव संसाधन का पुनर्संतुलन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में असमानता प्रायः रोजगार, शिक्षा और आवास क्षमता पर दबाव डालती है। देश में बढ़ती जनसंख्या एवं जनसंख्या के असंतुलन से नगरों एवं शहरों में भीड़, सेवाओं पर भार और बुनियादी ढांचे की कमी बढ़ी है। हालांकि जनसंख्या को केवल बोझ की तरह देखना एकतरफ़ा दृष्टि है। जनसंख्या का अगर सही उपयोग हो, सही शिक्षा-कौशल मिले, स्वास्थ्य बेहतर हो और अवसर उपलब्ध हों, तो जनसंख्या एक बोझ नहीं, बल्कि एक संसाधन बन जाती है।

उन्होंने समाज में परिवार की भूमिका को सामने रखते हुए कहा कि परिवार केवल जनसंख्या की इकाई नहीं, बल्कि समाजीकरण की पहली पाठशाला है। प्रत्येक बच्चे को व्यवहार, सहयोग, अहंभाव का नियंत्रण, सामाजिक कौशल जैसे संस्कार परिवार से मिलते हैं। इसलिए परिवार में संख्या का संतुलन आवश्यक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व के कई समाजों में जनसंख्या इतनी कम हो गई कि उनका विस्तार रुक गया और कई भाषाएं इसीलिए लुप्त हो गईं क्योंकि उन्हें बोलने वाले ही नहीं बचे। ऐसे में जहां बहुत अधिक जनसंख्या एक बड़ी चुनौती है, वहीं जनसंख्या का अत्यंत कम होना भी संकट है।

उन्होंने कहा कि जनसंख्या के विषय में बनाई जाने वाली नीतियां एक समग्र दृष्टि, मानव विकास, परिवार, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण क्षमता और भविष्य की आर्थिक आवश्यकता आदि सभी को जोड़कर बनाई जानी चाहिए। आज समाज में 'दो बच्चों का परिवार' एक आदर्श मॉडल के रूप में चर्चा में है। यह मॉडल कई देशों में लागू भी हुआ और वहां के सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे के लिए यह उपयुक्त भी है। इसके विपरीत भारत में जनसंख्या की गणना में सामाजिक दृष्टि से भी ध्यान देना होगा क्योंकि भारत के सामाजिक ताने-बाने की जड़ में रिश्ते, परिवार, संस्कार और विस्तृत कुटुंब व्यवस्था है। इसलिए एक संतुलित दृष्टि रखनी होगी, जिससे न तो अत्यधिक जनसंख्या बोझ बने और न ही इतनी कम हो कि परिवार, संस्कार और रिश्तों का जीवंत ताना-बाना ही कमजोर हो जाए। उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति उसकी जनसंख्या नहीं, उसकी संतुलित और संस्कारित जनसंख्या है। भारत की विस्तृत सीमा केवल भौगोलिक रेखा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, संस्कृति, पहचान और सुरक्षा की अंतिम परिधि हैं।

इन सीमाओं की रक्षा केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि सीमा क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का संतुलन, जनसंख्या की सजगता और समाज की एकजुटता भी करती है। ऐसे में जनसांख्यिकीय परिवर्तन को गंभीरता से लेना होगा। भारत की सीमाओं के साथ ही भारत की सामाजिक और जनसांख्यिकीय संरचना को भी सुरक्षित रखना होगा। यही राष्ट्र-निर्माण की सच्ची आधारशिला है। ■

पारित हुए पांच प्रस्ताव

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में चार एवं राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में एक प्रस्ताव पारित किया गया। **राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में पारित प्रस्ताव** में कहा गया कि देश के युवाओं को समाज परिवर्तन का वाहक बनाना चाहिए। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश की उन्नति आर्थिक विकास के साथ समग्र सामाजिक परिवर्तन से ही संभव है। जब समाज के प्रत्येक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, तब राष्ट्र के विकास की मजबूत नींव तैयार होती है। भारत का युवा इस परिवर्तन का केवल दर्शक न रहते हुए सशक्त वाहक बने। वर्तमान युवा सुसंस्कृत परिवार, समरस समाज निर्माण, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति स्व के भाव से अनुशासित नागरिक के रूप में समाज परिवर्तन में अपनी भूमिका का निर्वहन करें।

प्रस्ताव में कहा गया है कि सामाजिक समरसता किसी भी विकसित राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता है। समाज में विभेद उत्पन्न करने वाले और राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले इन सभी कारकों से ऊपर उठकर समरस समाज के निर्माण में युवा अपनी महती भूमिका निभाए। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, जो संस्कार और शिक्षा का प्रथम विद्यालय है। परिवार में मिलने वाले संस्कार प्रमाणिकता, अनुशासन, करुणा और कर्तव्यबोध को जन्म देते हैं। परिवार की सद्भावपूर्ण संरचना समाज में नैतिक मूल्यों की नींव मजबूत करती है।

प्रस्ताव में पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करते हुए कहा गया कि सतत विकास तभी संभव होता है जब वह पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर किया जाए। भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था, जल संसाधन और जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण पर ही निर्भर है। भारत की स्व-आधारित जीवनशैली मन, बुद्धि, कर्म और उपभोग- चारों स्तरों पर आत्मनिर्भरता और स्थानीयता को महत्व देती है। स्व-भाषा-भूषा, भोजन-भजन, भवन और भ्रमण का आग्रह ही भारतीय स्वाभिमान का भाव जागृत करेगा। अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का पालन भी आवश्यक है। इसके प्रति नागरिक सजगता लाने हेतु युवा अपने स्तर पर विभिन्न जागरण कार्यक्रम चलाएं यह अपेक्षित है। सामाजिक समरसता से एकजुटता, पर्यावरण संरक्षण से सतत विकास, परिवार प्रबोधन से नैतिक शक्ति, स्व-आधारित जीवन शैली से आत्मनिर्भरता तथा नागरिक कर्तव्यों से लोकतांत्रिक मजबूती-इन सभी का संयुक्त प्रभाव भारत राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाएगा।

अधिवेशन में **सुरक्षा एवं अवैध घुसपैठ विषय पर पारित प्रस्ताव** में कहा गया कि दशकों से भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जारी घुसपैठ देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक सदभाव, आर्थिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के अन्य सीमावर्ती राज्यों के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों में भी जनसांख्यिकी असंतुलन, अपराधों में वृद्धि, भूमि अतिक्रमण और राजनीतिक हस्तक्षेप इसके स्पष्ट दुष्परिणाम हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से असम के अस्तित्व का संकट है। न्यायालय ने इसे "साइलेंट इन्वेजन" (Silent Invasion) की संज्ञा भी दी। अभाविप का मानना है कि बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ केवल एक राज्य या क्षेत्र की समस्या नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा है। अभाविप केंद्र सरकार से मांग करती है कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को देश भर में लागू करके मतदाता सूची को संशोधित कर घुसपैठियों को देश से बाहर निकाली जाए, भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तत्काल बाड़ का कार्य पूर्ण हो, सीमा सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण कर सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाए, फर्जी दस्तावेज बनाने और वितरित

करने वालों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर दंड दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए ताकि मामलों का त्वरित निपटारा हो सके, सरकारी भूमि, वन भूमि तथा चारागाह भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए और नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन अवश्य किया जाना चाहिए।

अधिवेशन में **प्राकृतिक आपदाओं को लेकर पारित प्रस्ताव** में कहा गया कि पश्चिम में हिंदूकुश एवं पूर्व में अरुणाचल तक फैला नगाधिराज हिमालय पर्वत के हिमाच्छादित शिखर, दुर्गम मार्ग, सघन पर्वतीय वन और अनेकों पर्वत एवं असंख्य पर्यटन स्थल भारत की सांस्कृतिक पहचान रहे हैं। अनादि काल से हिमालय क्षेत्र भारतवर्ष एवं विश्व के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। परंतु दुर्गम रास्तों और कठिन जलवायु के कारण यहां की ऊंचाइयों तक पहुंचना सदैव अत्यधिक कठिन रहा है। ऐसे में केंद्र एवं राज्य सरकारें हिमालय क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत व्यवस्था को सुदृढ़ कर इस क्षेत्र को सुगम बनाने तथा पर्यटन के माध्यम से यहां की अर्थव्यवस्था को द्रुत गति देने का प्रयास कर रहीं हैं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारत को पर्यावरण के अनुकूल संधारणीय विकास की अवधारणा पर सतत कार्य करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दशकों में मानवजनित गतिविधियों के तीव्र विस्तार से हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक खतरों को गंभीर एवं आवृत्तिमय बना दिया है। प्रस्ताव में समाज एवं सरकारों से आह्वान करते हुए कहा गया है कि भारतीय संस्कार मानव प्रकृति और पर्यावरण के बीच संतुलित व्यवहार का है। वर्तमान आवश्यकता के अनुसार विवेकशील विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रकृति संवर्धन,पर्यावरण हितैषी समाज का निर्माण वर्तमान समय की मांग है।

इसी तरह **एक अन्य प्रस्ताव में पर्याप्त वित्तीय आवंटन सहित देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक संरचना के अंतर्गत लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया**। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली पर समग्रता से विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के साथ ही स्कूली शिक्षा में संतोषजनक एवं उच्च शिक्षा में कतिपय प्रगति हुई है, किंतु आधारभूत संरचना, छात्र कल्याण योजनाओं एवं अनुसंधान आदि की दृष्टि से अनेक कार्य करणीय हैं, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन के साथ ही सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र को एक संरचना के अंतर्गत लाना आवश्यक है। शिक्षा क्षेत्र के लिए एकीकृत नियामक संस्थान के गठन के साथ ही शैक्षिक सुधार का एक महत्वपूर्ण चरण है एकीकृत शिक्षा प्रणाली जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुकूल है। अभाविप का मत है कि शिक्षा पर समग्र विचार के लिए सभी शैक्षिक संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाए तथा कुल बजट का दस प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए।

अधिवेशन में पारित **एक अन्य प्रस्ताव में भारतीय समाज से विभाजनकारी शक्तियों के विरुद्ध संगठित होने का आह्वान किया गया।** प्रस्ताव में कहा गया कि भारत की पहचान एकत्व में विविधता, संस्कृति की अखंडता और भारतीय नागरिकों की संविधान के प्रति आस्था की भावना में निहित है। विविध मत, पंथ, भाषाओं, परम्पराओं तथा उत्सवों के साथ भारतीय जनमानस की राष्ट्रीय भावना के प्रति अटूट निष्ठा ने राष्ट्रीय एकात्मता को सुदृढ़ किया है, किंतु आज इसे अनेक प्रकार से चुनौती देने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में राज्यों के मध्य सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है। अभाविप का मत है कि भारतीय भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं को एक-दूसरे का पूरक मानकर ही सशक्त भारत का निर्माण संभव है। अतः समाज विभेदों से ऊपर उठकर लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए संकल्पित हो तथा शासन-प्रशासन राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने वालों पर कार्यवाही करे। अभाविप का मानना है कि संस्थाओं की समयोचित आलोचना के साथ ही उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों का जिम्मेदाराना व्यवहार अपेक्षित है। संवैधानिक संस्थाओं में जनता का विश्वास ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और इसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। अभाविप समाज तथा विशेषकर विद्यार्थी-युवाओं से आह्वान करती है कि नकारात्मक विमर्श पर सत्य एवं तर्क आधारित विषयवस्तु को प्रसारित कर अपनी भूमिका का निर्वहन करें एवं विभाजनकारी ताकतों के विरुद्ध संगठित होकर "राष्ट्र प्रथम" की भावना के साथ भारत को एक आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। ■

‘स्क्रीन टाइम’ कम करके ‘नेशन टाइम’ बढ़ाए युवा : श्रीकृष्ण पांडेय

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में ‘स्माइल रोटी बैंक फाउंडेशन’ के अध्यक्ष श्रीकृष्ण पाण्डेय ‘आजाद’ (गोरखपुर) को प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें एक लाख रुपए की धनराशि, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया। युवा पुरस्कार-2025 के लिए चयनित श्रीकृष्ण पाण्डेय ‘आजाद’ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा आसपास के जिलों के दो हजार से अधिक असहाय मनोरोगियों की सेवा तथा चिकित्सा सहायता प्रदान करके उनको नया जीवन दिया। साथ ही वह प्रदेश के विभिन्न जिला कारागारों में निरूद्ध बंदियों को परामर्श देने तथा विभिन्न प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के आयोजन से बंदियों की मनोदशा में परिवर्तन लाने और उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति छोड़कर समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय छात्रशक्ति से हुई विशेष वार्ता के दौरान उन्होंने अपने सामाजिक सरोकार, उद्देश्य एवं आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उनसे हुई वार्ता के प्रमुख अंश-

मनोरोगियों के लिए कार्य करने की शुरुआत कहां से हुई?

यह 17 जनवरी 2006 की बात है। एक सड़क दुर्घटना में वह बुरी तरह घायल हुए थे। सिर में लगी गंभीर चोट के कारण वह लंबे समय तक एक कमरे में बंद रहे। समाज से कटने के कारण मनोस्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। लेकिन ठीक होने के बाद मन में यह विचार आया कि ऐसे और भी लोग होंगे जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर सड़कों पर घूम रहे होंगे। बस इसके बाद उन्होंने कार्य आरम्भ किया।

कार्य का विस्तार किस प्रकार हुआ?

गोरखपुर जिले में मानसिक रोगी एवं बाल भिक्षुक की संख्या ज्यादा है। चूंकि गोरखपुर में मानसिक रोगियों के इलाज की बेहतर व्यवस्था है। लेकिन इलाज के लिए आने वाले लोग प्रायः मानसिक रोगियों को छोड़कर चले जाते हैं। हमने ऐसे रोगियों के लिए काम करना शुरू किया और फिर धीरे-धीरे विस्तार की प्रक्रिया बढ़ती चली गई और आज हमारे केंद्र में देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले मनोरोगियों का उपचार किया जा रहा है।

समाज से जुड़े कार्य में आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?

जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कठिनाई का होना स्वाभाविक है। इसे पार्ट ऑफ वर्क कहा जा सकता है। आरम्भ में समस्याएं एवं कठिनाई आई लेकिन धीरे-धीरे उनका समाधान होता चला गया।

अभी आपके कार्य की क्या स्थिति है ?

अभी गोरखपुर में दो केंद्र हैं। दोनों केंद्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई अन्य राज्यों से लाए गए रोगियों का उपचार किया जा रहा है। जहां से भी सूचना जाती है तो हमारी अपनी टीम वहां से रोगियों को लाती है। इसमें ऐसे भी रोगी होते हैं, जो सड़कों पर लावारिस की तरह पड़े होते हैं। हमारी टीम ने योजना बनाई है कि गोरखपुर के निकट एक वन क्षेत्र में कम से कम 500 मानसिक रोगियों वाले आश्रम को बनाकर वहां पर बेसहारों के रहने, भोजन एवं उपचार की व्यवस्था की जाए। यही मेरा अगला लक्ष्य है। आश्रम में मानसिक रोगियों का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा मुझे भरोसा है।

आपके कार्यों के लिए समाज से क्या मदद मिलती है?

निश्चित रूप से समाज के सक्षम लोग अपने-अपने स्तर पर हमारी मदद कर रहे हैं। एक संस्था ने हमें एम्बुलेंस दी, तो अन्य लोगों ने संस्था के संसाधन जुटाने में अपना योगदान किया। समाज के सक्षम लोगों की मदद से ही हम यह कार्य कर पा रहे है।

आगामी योजना क्या है?

लक्ष्य यही है कि देश में भी कोई ऐसा बेसहारा आदमी जो कहीं सड़क में पड़ा हो, उसे हर प्रकार की मदद मिलनी चाहिए। इस लिए मानसिक रोगियों के लिए और भी ज्यादा काम करना होगा। लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस कार्य में वह अपना सहयोग प्रदान करें। भारत में मानसिक रोगियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। अभी दो केंद्र चला रहे हैं। लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि केंद्रों की संख्या ज्यादा न हो, बल्कि जो भी केंद्र हों वह बड़े केंद्र हों और वहां हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए। देश में एक ऐसा तंत्र भी होना चाहिए जो मानसिक रोगियों की वास्तव में पहचान करके उन्हें आवश्यक उपचार देने की प्रक्रिया से जुड़ा होना चाहिए। कारण यह है कि भारत में होने वाली आतंकी घटनाओं के दोषियों को भी मानसिक रोगी बताकर बचाने का प्रयास किया जाता है। इसका स्पष्ट उदाहरण गोरखपुर में मंदिर पर हुए हमले में देखा गया, जहां दोषी को उसके घर वाले अनेक कागजों के माध्यम से मानसिक रोगी सिद्ध करने में जुटे रहे। कथित मानसिक रोग की आड़ में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाना एक चिंताजनक विषय है और इसके लिए एक तंत्र अवश्य बनाया जाना चाहिए।

आपकी टीम में अभी कितने लोग कार्य कर रहे हैं?

अभी लगभग 150 कार्यकर्ता हैं। इनमें से तीस ऐसे लोग है, जो पूर्ण रूप से संस्था का कार्य कर रहे हैं। टीम के साथ ही अन्य लोगों का सहयोग भी मिलता रहता है।

मनोरोग बढ़ाने में सोशल मीडिया की क्या भूमिका देखते हैं?

देश में उच्च-शिक्षित युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृति बहुत चिंताजनक विषय है। इसमें सोशल मीडिया की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। देश के आधुनिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नैतिक शिक्षा शायद नहीं दी जाती है। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित स्कूलों में बच्चे को वह संस्कार नहीं मिलते हैं, जो मिलने चाहिए। इसलिए बच्चों को प्राइमरी स्कूलों से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा के साथ सांस्कृतिक ज्ञान देने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा के लिए संस्कृति और नैतिक शिक्षा आवश्यक है। इसके अलावा संयुक्त परिवार का टूटना भी मानसिक रोग बढ़ाने का काम कर रहा है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?

युवाओं से कहना चाहूंगा कि वह अपना "स्क्रीन टाइम" कम करके "नेशन टाइम" को बढ़ाने पर ध्यान दें तभी वह निश्चित रूप से दूसरों की स्क्रीन पर दिखने लगेंगे और भारत पूर्ण रूप से विकसित हो सकेगा। ■

राष्ट्रीय पदाधिकारी (2025-2026)

राष्ट्रीय अध्यक्ष	डा. रघुराज किशोर तिवारी (रीवा)
राष्ट्रीय महामंत्री	डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी (इंदौर)
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	1. डा. एम नागलिंगम (कासरगोड)
	2. डा. आशुतोष मंडावी (रायपुर)
	3. डा. मंदार भानुषे (मुंबई)
	4. डा. सुरभि बेन दवे (जामनगर)
राष्ट्रीय मंत्री	1. श्री श्रवण बी राज (भाग्यनगर)
	2. श्री कमलेश सिंह (शिलोंग)
	3. सुश्री क्षमा शर्मा (नोएडा)
	4. श्री आदित्य तकियार (चंडीगढ़)
	5. सुश्री पायल किनाके (नागपुर)
	6. श्री अभय प्रताप सिंह (वाराणसी)
	7. श्री हर्षित निनोमा (बांसवाड़ा)
राष्ट्रीय संगठन मंत्री	श्री आशीष चौहान (मुंबई)
राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री	1. श्री गोविंद नायक (कोलकाता)
	2. श्री एस. बालकृष्ण (भाग्यनगर)
	3. श्री देवदत्त जोशी (मुंबई)
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष	श्री गीतेश सामंत (ठाणे)
राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष	श्री दयानंद भाटिया (जबलपुर)
केंद्रीय कार्यालय मंत्री	श्री सौरभ पाण्डेय (मुंबई)
केंद्रीय सचिवालय सचिव	श्री देवानंद त्यागी (मुंबई)
केंद्रीय सह-सचिवालय सचिव	श्री गौरव राजावत (मुंबई)

राष्ट्र का उद्घोषक मंत्र है एकात्मता स्तोत्र

■ मनीष कुमार

देवभूमि भारत को अनेक महान तपस्वी, ऋषि- मुनियों एवं महापुरुषों ने अपनी कठोर साधना से प्राप्त दिव्य शक्तियों से सींचा है। अपने इष्ट देवों, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव सभी पीढ़ियां रखती आई हैं, ताकि अपने पूर्वजों के समान ही साधक बन सके, आचरण कर सकें, उनके द्वारा बताए या दिखाए मार्ग पर चल सकें। इसके लिए आवश्यक था कि उनका नित्य प्रति स्मरण किया जाए, जिसके लिए श्लोकों और मंत्रों का निर्माण किया गया। इन श्लोकों और मंत्रों के माध्यम से अपने पूर्वजों एवं महापुरुषों को स्मरण रखने की एक सुदीर्घ परंपरा देश में देखने को मिलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रा.स्व.सं) इसी परंपरा की भूमि में पनपा एक बीज है। रा.स्व.सं अपने स्थापना काल से इस परंपरा का निर्वहन करता चला आ रहा है।

आरम्भ में इसे 'प्रातः स्मरण स्तोत्र' कहा जाता था। इसका अर्थ प्रातः जागरण के पश्चात किसी अन्य कार्य को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर या पूर्वजों के नाम का स्मरण करना होता है। आरंभ के प्रातः स्मरण स्तोत्र में कुल छह स्तोत्र थे। पहला, हस्त-दर्शन श्लोक, जिसमें बताया गया कि हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में गोविंद का निवास होता है। दूसरे श्लोक में पृथ्वी माता से क्षमा प्रार्थना की गई, तीसरे श्लोक में त्रि-देवों और नव-ग्रहों का आह्वान किया गया। इसी प्रकार चौथे श्लोक में सातों चिरंजीवी (अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम) का स्मरण एवं पांचवें श्लोक में सातों चिरंजीवियों के साथ-साथ आठवें महर्षि मार्कण्डेय का स्मरण करने के लिए बताया गया, जिससे अपमृत्यु से बचा जा सके। छठे श्लोक में सभी पांचों स्तोत्रों के नित्य पाठ से फल प्राप्ति के बारे में बताया गया है।

ऐसा माना गया है कि प्रातः स्मरण स्तोत्र वैदिकोत्तर काल में प्रचलित हुआ क्योंकि उसमें वैदिक देवताओं (सूर्य, अग्नि, इंद्र, सोम, वरूण आदि) का उल्लेख न होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी आदि के साथ-साथ भारत का भी परोक्ष रूप से उल्लेख किया गया है। प्राचीन

काल में भारतीय समाज अपने उच्च आदर्शों एवं धर्मानुसार आचरण करते हुए संचालित होता था। इसलिए आरंभिक प्रातः स्मरण श्लोक में तपस्वी ऋषि-मुनियों के नामों का वर्णन मिलता है। कालांतर में समाज अपने आदर्शों और धर्म से च्युत होने के कारण दोष-ग्रस्त हो गया। ऐसे में देश के तपस्वी ऋषि-मुनियों, महापुरुषों के साथ-ही-साथ इस मिट्टी के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति भाव में कमी न हो, इसीलिए पुराने छह श्लोकों के साथ-साथ राष्ट्र के श्रेष्ठ महापुरुषों के नामों का भी समावेश प्रातः स्मरण में किया गया।

रा. स्व. संघ अपनी स्थापना के बाद से ही राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए अनवरत रूप से हिंदू समाज को संगठित करते हुए नैसर्गिक रूप से हिन्दू समाज का ही अभिन्न संगठन बन गया। परिणामस्वरूप हिन्दू समाज के नागरिक ही स्वयंसेवक बने। राष्ट्र के महान ऋषि-मुनियों,

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के बाद से ही राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए अनवरत रूप से हिंदू समाज को संगठित करते हुए नैसर्गिक रूप से हिन्दू समाज का ही अभिन्न संगठन बन गया। परिणामस्वरूप हिन्दू समाज के नागरिक ही स्वयंसेवक बने।

महापुरुषों तथा महान भारत भूमि के प्रति सेवा, समर्पण एवं श्रद्धा के भाव में कभी कोई न्यूनता न आने पाए, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए रा. स्व. संघ के प्रथम प्रचारक बाबा साहब आप्टे ने 1951 में प्रातः स्मरण का संकलन किया।

पारम्परिक प्रातः स्मरण, जिसे आदिगुरू श्रीशंकराचार्य ने पंचायतन पूजा (सम्प्रदायों के समन्वय के लिए) के लिए तैयार किया था, जो लगभग 40-45 श्लोकों का स्तोत्र था, उसमें थोड़ा संशोधन करके रा. स्व. संघ में 45 श्लोकों के प्रातःस्मरण को आकार दिया गया। 1966 में नागपुर के ही सुप्रसिद्ध विद्वान वर्णेकर ने इसे पुनः संशोधित एवं सुव्यवस्थित कर इसका नाम 'भारत-भक्ति-स्तोत्र' कर दिया। इस पुण्य भूमि भारत में अनगिनत महापुरुषों ने जन्म लिया। उन सभी महापुरुषों का वर्णन प्रातः स्मरण के इस लघुरूप में कर पाना संभव नहीं हो पाया।

रा. स्व. संघ के सरसंघचालक (द्वितीय) ने प्रातःस्मरण या भारत-भक्ति स्तोत्र में अवर्णित महापुरुषों के संबंध में कहा था कि जिन महापुरुषों का उल्लेख इसमें नहीं है, उनके प्रति न्यून श्रद्धा होने का कोई कारण नहीं है। 1983 में रा. स्व. संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में नए एकात्मता स्तोत्र का अनुमोदन किया गया। इसके बाद दो श्लोकों में आंशिक परिवर्तन के पश्चात इसे स्वीकार कर लिया गया। परिवर्तित एकात्मता स्तोत्र को लिखने के लिए सुदर्शन जी एवं शेषाद्रि जी ने देशभर में प्रवास करके अलग-अलग महापुरुषों की श्रृंखला तैयार की तथा पर्याप्त चिंतन के पश्चात उन्हें जोड़कर अंतिम रूप दिया। वर्तमान एकात्मता स्तोत्र के स्वरूप को अंतिम रूप देने के बाद सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यह एकात्मता स्तोत्र, केवल श्लोक मात्र नहीं है अपितु यह राष्ट्र का उद्घोषक मंत्र है। ■

[वर्तमान एकात्मता-स्तोत्र को अनुष्टुप छन्द (प्रत्येक पाद में 8 वर्ण) में लिखा गया है एवं 32वां श्लोक शिखरिणी छंद (प्रत्येक पाद में 17 वर्ण) में लिखा गया है।]

सुधी पाठकों !

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' दिसम्बर-2025 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों एवं खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

विश्वविद्यालयों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों में आतंकी मॉड्यूल : एक भू-राजनीतिक चेतावनी

■ डा. रविंद्र प्रताप सिंह

10 नवंबर 2025 को देश की राजधानी दिल्ली में हुए आत्मघाती कार विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई और बीस से अधिक घायल हो गए। महत्वपूर्ण यह है कि यह आत्मघाती हमला किसी अनपढ़ या बेरोजगार मुस्लिम युवक ने नहीं, बल्कि एक उच्च शिक्षित डा. उमर उल नबी ने अंजाम दिया, जो अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज में सहायक प्रोफेसर था। साथ ही यह घटना शैक्षणिक रूप से उन्नत पेशेवरों और उच्च शिक्षित व्यक्तियों, जिनमें डाक्टर, इंजीनियर, सहायक प्रोफेसर और मेडिकल छात्र शामिल हैं, के एक व्यापक नेटवर्क को भी उजागर करती है। सुरक्षा एजेंसियों ने जितने भी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया हैं, वह सभी ऐसे पेशेवर लोग है, जिन्हें सामान्यतः समाज में सफल और आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है।

इस आतंकी मॉड्यूल का संचालन फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय से किया जा रहा था, जहां से सहायक प्रोफेसर डा. मुज़म्मिल अहमद गनाई को गत अक्टूबर माह में गिरफ्तार किया गया। यह मॉड्यूल न केवल देश में आतंकी विचारधारा का प्रचार कर रहा था, बल्कि हथियारों, विस्फोटक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अवैध भंडारण करने के लिए विश्वविद्यालय से सम्बंधित आवासों और किराए के फ्लैटों का उपयोग कर रहा था। अल-फलाह मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद वागे, पाकिस्तान में बैठकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर उमर बिन खत्ताब के साथ एन्क्रिप्टेड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सीधे संपर्क में था। अदील राथर का भाई डा. मुजफ्फर अहमद राथर, जो अफगानिस्तान में डेरा डाले हुए है, कश्मीर सेल और अफगानिस्तान स्थित जैश के मॉड्यूल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता रहा है। इससे पता चलता है कि दूरस्थ जेहादी समूह लगातार भारतीय नागरिकों को भर्ती करके भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं।

अल-फलाह विश्वविद्यालय न केवल आतंकवादी गतिविधियों को छिपाने के लिए 'शरणस्थली ' के रूप में कार्य कर रहा था, बल्कि इसकी वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी संदेह के दायरे में हैं। जांच के दौरान अवैध विदेशी मुद्रा और धन-शोधन के आरोप भी सामने आए हैं, जो हवाला नेटवर्क के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण में संगठित अपराध की गहन भागीदारी को दर्शाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने संस्थान के फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से लेकर अन्य सभी निकायों ने इस विश्वविद्यालय की निगरानी एवं मूल्याङ्कन कैसे और किस आधार पर किया, यह भी गहन जांच का विषय है।

जांच का दायरा बढ़ रहा है और यह केंद्र सरकार एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर तात्कालिक चुनौती बनता जा रहा है। साथ ही यह शैक्षणिक संस्थान देश के आंतरिक सूचनातंत्र की विफलता और आतंकी तत्वों द्वारा संस्थागत स्थान के दुरुपयोग को भी दर्शाता है। यह घटना देश की आंतरिक सुरक्षा के विमर्श में एक महत्वपूर्ण गुणात्मक बदलाव भी लाई है। अब यह स्पष्ट है कि आतंकवादी और विद्रोही गतिविधि का खतरा जम्मू एवं कश्मीर के ग्रामीण या सीमांत क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और पेशेवर विशेषज्ञता के उच्च अल्पसंख्यक संस्थानों के परिसरों में गुप्त तरीके से पोषित हो रहा है।

भारत में 'सफेदपोश आतंकवाद मॉड्यूल' का यह ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें अब मुस्लिम वर्ग के उच्च

शिक्षित डाक्टर, इंजीनियर तथा प्रोफेसर शामिल हो रहे है। यह घटनाक्रम केवल कानून और सुरक्षा मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह देश में पनपते इस्लामिक आतंकवाद को मिलते राजनीतिक संरक्षण के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में फैलते आतंकी नेटवर्क के विस्तार से भी जुड़ा हुआ है। यह देश की संस्थागत अखंडता के क्षरण की एक नई भयावहता को दर्शाता है, जिसे एक बहु-आयामी सैद्धांतिक और नीतिगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

जिस प्रकार से इस हमले के बाद जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला से लेकर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेताओं तथा मौलवियों ने दिखावटी आलोचना की आड़ में इन आतंकियों को समर्थन देने के लिए कश्मीर से

देश के प्रमुख अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, परिसर में राजनीतिक सक्रियता और जेहादी गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थान, जहां छात्र राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विचारों पर विमर्श करते हैं, आज आतंकवाद तथा अतिवादी विचारधाराओं के लिए भर्ती का केंद्र बनते जा रहे हैं।

सम्बंधित धारा-370 के विलोपन को आधार बनाया है वह अपने आप में पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। डा. नबी, जिसे उसका परिवार गरीबी से बाहर आने की अपनी एकमात्र आशा बता रहा था, वह सबसे अधिक कट्टरपंथी था और आत्मघाती हमलावर बनने के लिए मानसिक तौर पर भी तैयार था। यह प्रदर्शित करता है कि कट्टरपन से जुड़ी यह घटना अशिक्षा, बेरोजगारी या आर्थिक अभाव का परिणाम नहीं है और यह मुस्लिम युवाओं में तेजी से पनपती जेहादी विचारधारा का परिणाम है।

दिल्ली में हुई आतंकी घटना के स्वरूप पर ध्यान दिया जाए, तो यह उन पिछली घटनाओं से मेल खाता है, जहां आतंकवाद के आयोजक प्रायः शिक्षित मध्यम वर्ग के सदस्य होते हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाला ओसामा बिन लादेन हो या फिर भारत की संसद पर हमला करने का साजिशकर्ता अफजल गुरु या फिर भारत में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी), अहल-ए-हदीस और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन चलाने वाले सभी शिक्षित वर्ग के रहे हैं। सिमी, जिसे 2001 में प्रतिबंधित किया गया था, को 'राष्ट्र-विरोधी' साहित्य का प्रसार करने तथा अल-कायदा तथा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेन्स से संबंध रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अल-फलाह मॉड्यूल में जैश और अंसार गजवत-उल-हिंद का आपसी गठजोड़ यह दर्शाता है कि भारत में विभिन्न राज्यों में आतंकी तत्वों में सहयोग की एक लंबी श्रृंखला चल रही है, जिसका उद्देश्य अस्थिरता फैलाना है।

प्रश्न यह है कि मुस्लिम वर्ग के उच्च शिक्षित युवा आखिर किससे प्रेरित हो रहे हैं? तो इसके लिए देश के अकादमिक विद्वानों की उस श्रृंखला पर भी ध्यान देना होगा, जिन्होंने भारत में साम्प्रदायिकता के अध्ययन लेखों के माध्यम से देश के युवाओं के सामने एक गढ़ा हुआ विमर्श (फैब्रिकेटेड नैरेटिव) प्रस्तुत किया है। सैंडी गॉर्डन, पॉल ब्रास, आशुतोष वार्ष्णेय, ज्ञानेंद्र पाण्डेय तथा राजीव भार्गवा जैसे वामपंथी विद्वानों नें अपने अकादमिक लेखनों के माध्यम से मुसलमानों के अन्दर पनपती इस कट्टरता को भारत में हिंदू राजनीति के उदय में चिह्नित किया है। उन्होंने यह दलील दी है कि दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और 2002 में गुजरात में हुए दंगे ने देश में मुस्लिमों के एक वर्ग को अलग-थलग कर दिया। इस्लामिक आतंकवाद को मिलने वाला यह अकादमिक संरक्षण बेहद ही चिंता का विषय रहा है। देश के लोग निवेदिता मेनन द्वारा 2016 में दिए गए उस भाषण को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें वह अरुणांचल प्रदेश, मणिपुर तथा जम्मू एवं कश्मीर के भारत से अलग होने की वकालत कर रही थीं।

वास्तव में देखा जाए तो देश के प्रमुख अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, परिसर में राजनीतिक सक्रियता और जेहादी गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थान, जहां छात्र राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विचारों पर विमर्श करते हैं, आज आतंकवाद तथा अतिवादी विचारधाराओं के लिए

भर्ती का केंद्र बनते जा रहे हैं। अतीत में भी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसे प्रमुख संस्थानों में अफजल गुरु मामले में और नागरिकता संशोधन अधिनियम (विधेयक) के विरोध में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान 'राष्ट्र-विरोधी' नारे लगाने या हिंसा भड़काने की घटनाएं हो चुकीं हैं।

जामिया जैसे संस्थानों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का "इस्लामीकरण" करने का प्रयास भी देखा गया, जब पांथिक नारे लगाए गए थे। यह विरोध-प्रदर्शन 'मुस्लिमों का विशुद्ध सांप्रदायिक प्रदर्शन' बन गया। यह छात्र आंदोलन की आड़ में उन लोगों को आकर्षित करने के लिए किया गया जो 'खिलाफत' पर यकीन रखते थे। यह राजनीतिक ध्रुवीकरण शैक्षणिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अखंडता के बीच की नाजुक रेखा को

शैक्षणिक संस्थाएं केवल विचार-विमर्श के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वह अब भारत की सुरक्षा के लिए एक संवेदनशील स्थान बनते जा रहे हैं। अल-फलाह मामला एक संस्थागत विफलता है, जो अलगाव, विदेशी प्रायोजन और आंतरिक दुर्भावना का गठजोड़ है। केंद्र सरकार को इन मॉड्यूल के संरचना को गहन चिंता के रूप में देखना चाहिए, जिसके लिए अकेले पुलिस कार्रवाई अपर्याप्त है।

धुंधला करता है। इन संस्थानों में विरोध प्रदर्शनों के बाद राजद्रोह या पोटा एवं यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत गिरफ्तारियां भी हुई। यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि सरकार स्वयं शैक्षणिक परिसर की देश विरोधी गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानती है। जेल में बंद जेएनयू से जुड़े उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे कथित छात्र नेताओं पर राजद्रोह और बाद में दिल्ली दंगों में संलिप्तता के आरोप हैं।

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आतंकवाद के मॉड्यूल का सफल संचालन भारत के लिए बाहरी भू-राजनीतिक खतरों की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। शिक्षण संस्थानों में आतंकवाद के मॉड्यूल का पाया जाना इस बात की चेतावनी है कि सरकार की आतंकवाद विरोधी रणनीति अब केवल बल प्रयोग या कानूनों पर केंद्रित नहीं रह सकती। इसके पीछे जुड़े हुए अंतर्निहित राजनीतिक, सामाजिक एवं कट्टरपन पनपाने वाले तत्वों के विरुद्ध सटीक एवं कठोर कार्रवाई करनी होगी, जो मुस्लिम युवाओं को आतंक की ओर धकेल रहे हैं।

केंद्र एवं राज्य सरकारों को अल-फलाह विश्वविद्यालय की तरह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संस्थानों के विरुद्ध निर्णायक एवं ठोस कदम उठाने चाहिए। मदरसों और अन्य संगठनों द्वारा विदेशी धन के उपयोग की जांच करने के लिए नए कानून बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जहां अल्पसंख्यक अधिकार के नाम पर शिक्षा को राष्ट्रद्रोह का माध्यम बनाने की कोशिश हो रही है, वहां अब निर्णायक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

संक्षेप में, विश्वविद्यालयों में आतंकवादी मॉड्यूल का पाया जाना एक उन्नत और अत्यधिक संक्रामक सिंड्रोम की तरह है। यदि पारंपरिक आतंकवाद एक बाहरी आक्रमण था, तो यह नया रूप एक स्वप्रतिरक्षित रोग है, जहां शरीर की सबसे शिक्षित और महत्वपूर्ण कोशिकाएं (डॉक्टर और प्रोफेसर) स्वयं ही शत्रु बन जाती हैं। इस रोग का इलाज केवल कठोर कानून से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए रोग की जड़ों को समझने (राजनीतिक अलगाव) और आंतरिक प्रतिरोधी तंत्र (संस्थागत अखंडता) को मजबूत करने की आवश्यकता है।

शैक्षणिक संस्थाएं केवल विचार-विमर्श के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वह अब भारत की सुरक्षा के लिए एक संवेदनशील स्थान बनते जा रहे हैं। अल-फलाह मामला एक संस्थागत विफलता है, जो अलगाव, विदेशी प्रायोजन और आंतरिक दुर्भावना का गठजोड़ है। केंद्र सरकार को इन मॉड्यूल की संरचना को गहन चिंता के रूप में देखना चाहिए, जिसके लिए अकेले पुलिस कार्रवाई अपर्याप्त है। इसके स्थान पर एक ऐसी सामरिक, बौद्धिक और सामाजिक नीति की आवश्यकता है, जो शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करे। ■

(लेखक, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं।)

India as an exporter of military hardware

■ K. N. Pandita

On May 12, 2020, Prime Minister Shri Narendra Modi formally launched the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, which, among other objectives, aims at self-reliance and minimizing dependence on importing defence equipment from foreign countries.

The proponents of the Atmanirbhar Bharat concept, including Modi and cabinet ministers for finance and law, said this self-reliance policy does not aim to be protectionist, exclusionist or isolationist. For India, self-reliance means being a larger and more important part of the world economy. The concept requires policies that are efficient and resilient and encourage equity and competitiveness. It means being self-sustaining and self-generating,and creating "wealth and values not only for ourselves but for the larger humanity. In March 2021, Finance Minister Nirmala Sitharaman had said that the Atmanirbhar Bharat campaign was not about bringing back socialism or import substitution; the intention has been to boost the manufacturing exercise. The five pillars of Atmanirbhar Bharat are economy, infrastructure, technology-driven systems, vibrant demography and demand.

The emphasis on self-reliance and initiativewas an indirect challenge to the DRDO and autonomous companies in the country that manufactured items of defence requirements. India's growing need for high-quality defence equipment, on the one hand and enormous foreign exchange required to purchase advanced military hardware, on the other, necessitated highlighting the importance of self-reliance, particularly in advanced military equipment. They reacted positively to the call of the Indian Defence Minister.

Indian Defence Minister Rajnath Singh shakes hands with his Indonesian counterpart SjafrieSjamsoeddin before the third India-Indonesia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi. (Photo : AFP)

This timely call and positive response from the public and private manufacturing sectors are now showing encouraging results. Several defence items,including heavy armour and air defence digital equipment are manufactured in India. India ismoving ahead to find a place among the leading exporters of military hardware.

Writing in the South Asia Voices, Anondeeta Chakraborty says that India's defence exports reached an all-time high of USD 2. 76 billion in FY 2024-25, " recording 12 per cent growth year on year." Today, India's private and public sector companies collectively export defence products to 100 countries worldwide.

India's defence exports to the United States exceeded USD $2.8 billion between 2019 and 2024, representing a small proportion of US arms imports but 50 per cent of India's total

defence exports in the same period. India's exports to the European Union from February 2022 to July 2024 surged owing to the Ukrainian war and surpassed USD $ 135 million. Indian manufacturing operatives have signed deals with their Western counterparts to bolster India's export potential. For example, Reliance has a USD $68 million scheme to produce artillery shells and explosives with Rheinmetall of Germany.

Defence analysts see New Delhi emerging as a serious alternative security partner for Southeast Asia, offering hi-tech arms without "hegemonic baggage," wrote my News of December 1, 2025.

During the third India-Indonesia Defence Ministers' Dialogue last week of November, the two sides discussed the supply of the Brahmos missile system to Jakarta. After the Philippines, Indonesia is the second Southeast Asian country pursuing the purchase of this missile system from India.

Reports are that the negotiations between the two countries have been completed. However, formal approval of Moscow is awaited. It should be remembered that Russia has a 49.5 per cent stake in the BrahMos joint venture. The BrahMos Aerospace is jointly owned by India's Defence Research and Development Organisation (DRDO) and Russia's NPO Mashinostroyenia.

India's arms contract with Indonesia, now in process, is interpreted variously by the commentators. For instance, one view is that it is a sign of India's growing defence export ambitions. "It is not just another arms contract: rather, it is India's strategic arrival in a region (Southeast Asia) where hard power has long been defined by the US and constrained by China's coercive posturing, says Gaurav Kumara, a researcher at the United Service Institution of India, a defence think tank.

The US $ 450 million Brahmos deal with India (now in process) follows the Philippines' US $ 375 million purchase in 2022. The deliveries began last year. Vietnam, another South Asian country, is reported to be in advanced talks over potential contracts estimated at US $ 700 million.

These moves and deals are bound to have an impact on security strategies in the South Asian region, where China has a strong naval presence. In an overall estimation, India will be profiled as an alternative defence player in Southeast Asia. Ivan Lidarev, a visiting research fellow at the National University of Singapore's Institute of South Asian Studies, asserts that the export of BrahMos missiles to Southeast Asia blends strategic and economic logic.

From a strategic point of view, these deals allow India to enhance its geopolitical and security role in the region and help its push to emerge as an internationalarms exporter. And in terms of economic advantage, concluding deals with the Southeast countries could mean that India intends to diversify its trade and economic partnerships and facilitate its emergence as a major international manufacturer as part of its 'Make in India' mission.

The significance of these deals for Southeast Asian countries is that they come without sanctions risks, without hegemonic baggage and without intrusive conditions. Jakarta wants to safeguard its position over the disputed areas, rather than the entire maritime domain, including the Natuna Sea, critical sea lanes and approaches to the Malacca Strait, said the foreign affairs analyst of This Week in Asia. Many Southeast Asian countries were tired of "being forced into a binary choice between Washington and Beijing."

India's defence exports reached a record 236.2 billion rupees ($ 2.64 billion) in 2024-25, up 12 per cent year on year. Defence Minister Rajnath Singh announced in October last that Delhi had signed more than 40 billion rupees worth of arms contracts in a single month without naming the clients, but it was widely understood to include Indonesia and Vietnam.

In the final analysis, the important outcome of India's entry as a global arms exporter, with focuson the Southeast Asian countries, where China and America both have strategic stakes and military build-ups, needs to be watched. Carefully. ■

(The author is the former Director of the Centre of Central Asian Studies, Kashmir University, Srinagar, India)

लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुद्धता में एसआईआर की भूमिका

■ निखिल रंजन

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहां लोकतंत्र का संचालन मतदाता और मतदान की प्रक्रिया के आधार पर होता है। इसकी मजबूती का आधार मतदाता सूची की शुद्धता और चुनाव की पारदर्शिता है। यदि मतदाता सूची में त्रुटि हों, मृत व्यक्तियों के नाम सम्मिलित रहें या फिर देश में रहने वाले अवैध नागरिकों के नाम शामिल हो जाएं तो यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। ऐसे में देश के चुनाव आयोग का दायित्व है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मताधिकार उपलब्ध कराए और किसी भी गैर-कानूनी तत्व को मतदाता सूची से बाहर रखे। इसके लिए समय-समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किए जाने का प्रावधान है। इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण रूप कई राज्यों में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को दूर करना है। यह मात्र प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता का स्तंभ है। लेकिन जब एसआईआर को राजनीतिक स्वार्थ के मुद्दे से जोड़ दिया जाता है, तब यह केवल प्रशासनिक प्रकिया का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विवाद का विषय बन जाता है। इसलिए एसआईआर और अवैध घुसपैठ के प्रश्न को बिना पूर्वाग्रह समझना आवश्यक है।

एसआईआर की आवश्यकता एवं उद्देश्य

एसआईआर का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मृत व्यक्तियों के नाम सूची में न रहें, स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सही स्थान पर दर्ज हों, दोहराव वाले नाम हटाकर जो योग्य नागरिक अब तक पंजीकृत नहीं हुए हैं, उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाए। इस प्रक्रिया में बूथ स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति करके प्रत्येक नागरिक के सत्यापन और दस्तावेजों की जांच की जाती है। यह मात्र तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक ईमानदारी को बनाए रखने का भी प्रयास है क्योंकि मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता का आधार है।

एसआईआर और राजनीतिक विवाद

हालांकि एसआईआर का उद्देश्य प्रशासनिक है, लेकिन कई राज्यों में यह राजनीतिक विवाद का केंद्र बन जाता है। विशेषकर उन राज्यों में जहां अवैध घुसपैठ के कारण जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा या बदल गया है। इसी कारण बाहरी लोगों का अवैध प्रवास सम्बन्धी मुद्दा संवेदनशील है। कुछ समुदायों को लगता है कि यह कार्रवाई उनके विरुद्ध लक्षित है। वर्तमान में सोशल मीडिया में आने वाली अफवाहें इस अविश्वास को और भड़काती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से तथ्य विहीन आंकड़े और संवेदनशील टिप्पणियां साझा की जाती हैं, जिससे लोकतांत्रिक संवाद कमजोर होता है।

चुनाव आयोग की चुनौती

चुनाव आयोग के सामने दोहरी चुनौती होती है। एक ओर उसे स्वतंत्रता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होती है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दबाव और सामाजिक तनाव में संतुलन बनाए रखना होता है। एसआईआर का उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली की ईमानदारी को बढ़ाना है। हालांकि वर्तमान विवाद ने अवैध बंगलादेशी घुसपैठ के मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित किया है।

बांग्लादेशी घुसपैठ बनी बहुआयामी समस्या

भारत के पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से होने वाली बांग्लादेशी घुसपैठ लंबे समय से एक गंभीर समस्या है। स्थानीय हिंदू समाज को अक्सर अवैध प्रवासियों के आने

से उनकी भूमि, संसाधन और रोजगार पर दबाव को झेलना पड़ता है। सांस्कृतिक पहचान और जनसांख्यिकीय संतुलन भी प्रभावित होता है, जो सामाजिक तनाव उत्पन्न करता है। इस पृष्ठभूमि में यदि किसी प्रक्रिया या पहल, जैसे कि एसआईआर के माध्यम से अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, तो इसे सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए।

भारत में अवैध रूप से होने वाली बांग्लादेशी घुसपैठ केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी व्यापक असर डालती है। बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों के आने से स्थानीय श्रम बाजार पर दबाव बढ़ता है, भूमि और संसाधनों की प्रतिस्पर्धा तेज होती है और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चिंता गहराती हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह मुद्दा मतदाता सूची विवाद और चुनावी ध्रुवीकरण का कारण बन जाता है और इससे मानवाधिकार के संदर्भ में शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया और इसके साथ भारत की पूर्वी सीमा, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय और असम शामिल हैं, लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदियों, झीलों, दलदली मैदानों और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जहां निगरानी करना अत्यंत कठिन है। यही कारण है कि अवैध घुसपैठ की समस्या वर्षों से लगातार जारी रही और समय के साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन होता गया।

भारत में अवैध घुसपैठ का इतिहास तीन महत्वपूर्ण कालखंडों में समझा जा सकता है। पहला कालखंड 1971 के युद्ध और विस्थापन का है, जब लाखों शरणार्थी मानवीय आधार पर भारत आए। इस समय वास्तविक शरणार्थियों और स्थायी प्रवासियों के बीच अंतर करना कठिन हो गया और कई लोग स्थायी रूप से भारत में बस गए। दूसरा कालखंड 1980 से 1990 के दशक का रहा, जब आर्थिक पलायन प्रमुख कारण बना। गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं, जनसंख्या का दबाव और खुली सीमाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग कृषि, निर्माण और श्रम कार्य के लिए भारत आए। तीसरा कालखंड 2000 के बाद का है, जब अवैध रूप से होने वाली घुसपैठ केवल आर्थिक या मानवीय समस्या नहीं रही, बल्कि सुरक्षा संदर्भ भी जुड़ने लगी। इस अवधि में अवैध आव्रजन के साथ नकली मुद्रा, तस्करी और आतंकी तंत्र के उपयोग की घटनाएं भी सामने आईं।

अवैध घुसपैठ का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ का परिप्रेक्ष्य केवल जनसंख्या के दबाव या आर्थिक अवसरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवीय, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सम्मिलित रूप है, जिसने भारत के पूर्वोत्तर सहित कई राज्यों की स्थिरता और नीतिगत चिंताओं को गहराई से प्रभावित किया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ एक जटिल और बहुआयामी समस्या रही है, जिसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया है। असम में 1980 के दशक के दौरान अवैध घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय असंतुलन की चिंता बढ़ी। स्थानीय निवासियों को लगा कि उनकी पहचान और संसाधनों पर बाहरी लोगों का दबाव बढ़ रहा है। यही विवाद आगे चलकर 1985 के असम समझौते तक पहुंचा और बाद में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जैसी पहल सामने आई, जिसका उद्देश्य नागरिकता की स्पष्टता और घुसपैठ पर नियंत्रण था।

इसी तरह पश्चिम बंगाल की स्थिति सांस्कृतिक और भाषाई समानताओं के कारण अलग रही है। यहां सीमा पार से होने वाली गतिविधि अपेक्षाकृत अधिक रही और अवैध बांग्लादेशी नागरिक विशेषकर निर्माण क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यरत पाए गए। इससे स्थानीय श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और मजदूरी दरों पर दबाव पड़ा।

त्रिपुरा में प्रवास का इतिहास और भी गहरा है। यहां लगभग साठ प्रतिशत सीमावर्ती जनसंख्या किसी न किसी रूप में अवैध घुसपैठ से प्रभावित रही है। यही कारण है कि त्रिपुरा में राजनीतिक तनाव और पहचान की राजनीति अधिक दिखाई देती है। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार के उत्तर-पूर्वी जिलों की है।

एसआईआर का विरोध क्यों

आखिरकार, लोकतंत्र की सच्ची ताकत चुनावी प्रक्रिया पर जनता के विश्वास में निहित है और यह विश्वास तभी सुदृढ़ होगा, जब मतदाता सूची सही, निष्पक्ष और सटीक होगी, चाहे इसके लिए एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से गहन संशोधन की आवश्यकता क्यों न करनी पड़े। भारत के

पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय हिंदू नागरिक प्रायः इसलिए चिंतित रहता है कि अवैध प्रवासियों के आने से उनकी भूमि, संसाधन और रोजगार पर दबाव बढ़ता है। इससे क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान और जनसांख्यिकीय संतुलन भी प्रभावित होता है, जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे में एसआईआर के माध्यम से अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, तो इसे सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए। अवैध प्रवासियों की पहचान से न केवल स्थानीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होंगे, बल्कि संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग भी सुनिश्चित होगा। इससे रोजगार के अवसरों में प्रतिस्पर्धा कम होगी और भूमि पर दबाव घटेगा।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची में अवैध नागरिकों के नाम को हटाने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। सुरक्षा के स्तर पर भी यह पहल सहायक होगी क्योंकि अवैध घुसपैठ के साथ नकली मुद्रा, तस्करी और अन्य अपराध भी पोषित होते हैं। इस दृष्टि से एसआईआर जैसी प्रक्रिया से अगर अवैध घुसपैठियों की पहचान हो रही है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह कदम न केवल स्थानीय हिंदू नागरिकों की चिंताओं को कम करेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, सांस्कृतिक संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगा।

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ और अभाविप

अभाविप के आंदोलन के कारण 2008 में पहली बार केंद्र सरकार ने यह स्वीकार किया था कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ देश के लिए बड़ा खतरा है। जानकारी हो कि 17 दिसंबर 2008 को किशनगंज (बिहार) के रूईधासा मैदान में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने विशाल सभा एवं रैली का आयोजन किया था। अभाविप ने "चलो चिकेन नेक" की हुंकार लगाई थी, जिसमें देश भर से आए तीस हजार से अधिक छात्र-छात्राएं एवं दस हजार से अधिक स्थानीय जनता ने हिस्सा लिया। अभाविप ने इस रैली में मांग की थी कि भारत-बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह से बंद करके सीमा सुरक्षा बल को व्यापक अधिकार दिए जाएं। साथ ही अवैध घुसपैठ के संदर्भ में "डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट" की नीति अपनाने के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित मदरसों, मस्जिदों एवं धार्मिक स्थलों की जांच अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए स्वतंत्र टास्क फोर्स बनाने की मांग की थी। किशनगंज की रैली के निमित्त लगभग एक वर्ष चले अभियान ने महाविद्यालयों में घुसपैठ के संकट के बारे में छात्रों में काफी जागृति लाई। परिणामस्वरूप देश के कई महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की परिसर में सभाएं हुई और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजे गए।

जिस समय किशनगंज में सभा हो रही थी, उसी समय देश के प्रमुख शहरों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध प्रदर्शन भी हुए। अभाविप के आंदोलन का प्रभाव यह भी था कि तत्कालीन समय में संसद के दोनों सदनों में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठा और जवाब मांगा गया। जानकर आश्चर्य होगा कि पहली बार देश की तत्कालीन सरकार ने यह स्वीकार किया था कि बांग्लादेश की सीमा से होने वाली अवैध घुसपैठ भारत के लिए खतरा पैदा कर रही है।

निष्कर्ष

भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की दृढ़ता मतदाता सूची की शुद्धता पर निर्भर है। एसआईआर जैसी प्रक्रिया चुनावी प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाती है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुआयामी चुनौती है, जिसे केवल सुरक्षा नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी देखना होगा। इसका समाधान ठोस नीतियों और प्रशासनिक सुधार से निकाले जाने के साथ ही एसआईआर जैसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण एसआईआर का किए जाने वाले विरोध को उचित नहीं ठहराया जा सकता। देश में एसआईआर जैसी व्यवस्था से अवैध घुसपैठियों की पहचान हो रही है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। यह कदम न केवल स्थानीय समाज की चिंताओं को कम करेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, सांस्कृतिक संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगा।

भारत का लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है, जब मतदाता सूची शुद्ध, अद्यतन और सटीक हो। एसआईआर इस दिशा में उठाया गया सार्थक कदम है। इसे राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग देकर देखना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास है। यह विश्वास तभी मजबूत होगा, जब मतदान प्रक्रिया पारदर्शी और मतदाता सूची निष्पक्ष होगी। एसआईआर इसी विश्वास की नींव को मजबूत करता है। ■

(लेखक, अभाविप के पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं।)

देहरादून : ध्वजारोहण करते हुए अभाविप के निवर्तमान अध्यक्ष डा. राजशरण शाही एवं राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी

'यशवंत@100' पुस्तक का विमोचन करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. रघुराज किशोर तिवारी, महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष डा.राजशरण शाही एवं केंद्रीय सचिवालय सचिव देवानंद त्यागी

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 DECEMBER, 2025
DATE OF PUBLISHING: 8 DECEMBER, 2025
POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26

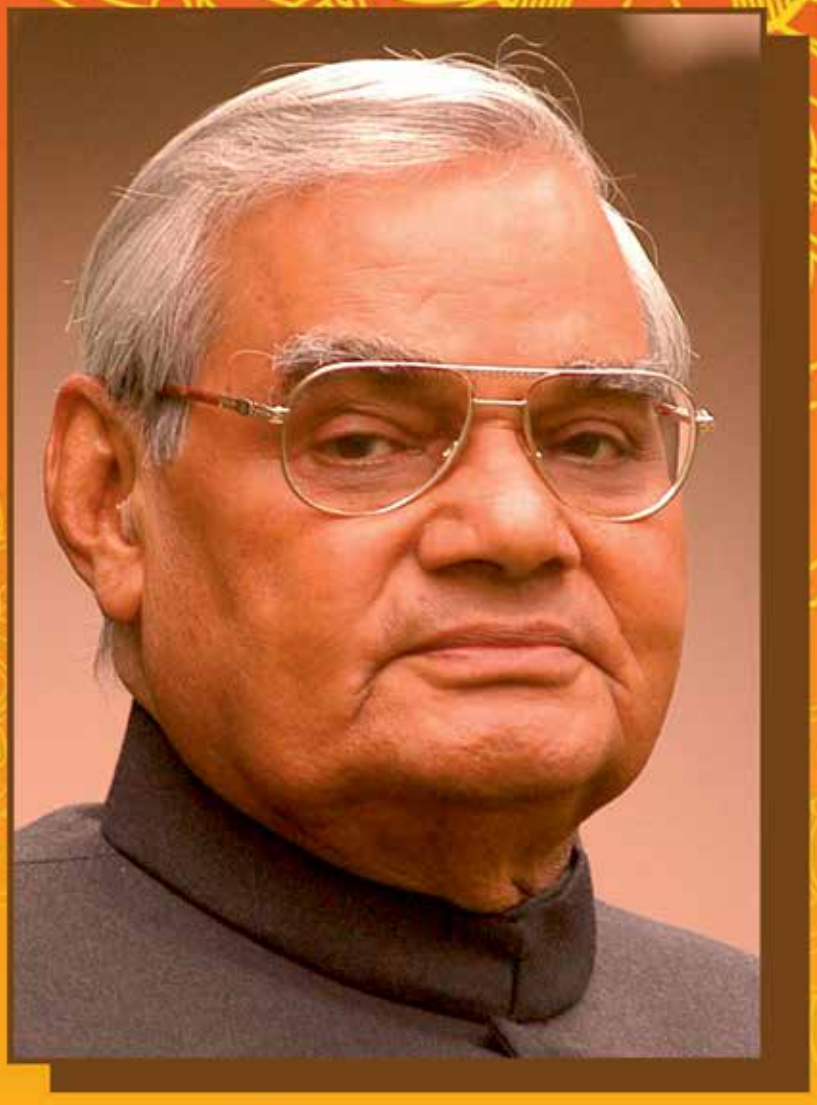

भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, संवेदनशील कवि एवं कुशल प्रशासक के रूप में भारत ही नहीं, अपितु विश्व में लोकप्रिय रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परीषद् का उनके साथ एक अन्य संबंध भी रहा जो अल्पज्ञात है। स्वर्गीय वाजपेयी अभाविप द्वारा स्थापना के समय चलाए गए पहले राष्ट्रीय अभियान, जिसे भारतीयकरण उद्योग का नाम दिया गया था, की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रहे। जन्मशती सम्पूर्ति के अवसर पर परिषद कार्यकर्ताओं की ओर से शत्-शत् श्रद्धांजलि!